# HRA Sazette of India

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्डा 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY 13/10/98

सं॰ 118] No. 118] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 1998/ ज्येष्ठ 12, 1920 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 1998/JYAISTHA 12, 1920

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

( बजट अनुभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1998

सं. एफ. 15 ( 10 )-ब्री ( डी )/98.-- निम्नलिखित सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है :

बजट 1998-99

वित्त मंत्री

श्री यशवन्त सिन्हा

का

भाषण

1 जून, 1998

भाग 'क'

मान्यवर,

मैं वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

### प्रस्तावना

- 2. प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट है। यह इतिहास का एक निर्णायक क्षण है। यह वह अवसर है जो आशाओं से परिपूर्ण है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का उस विश्वास एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूं जो उन्होंने मुझे प्रदान किया है।
- 3. इस सरकार को शासन की बागडोर संभाले हुए दस से कुछ अधिक सप्ताह ही हुए हैं। परन्तु हम जान गए हैं कि अब एक नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। 11 मई का दिन निश्चित रूप से पहला कदम था और आज यह दूसरा कदम है। वस्तुत: हमें आगे एक लम्बी यात्रा तय करनी है परन्तु इतिहास इस बात को सिद्ध करेगा कि हमने अब एक नए भारत का निर्माण शुरू कर दिया है। यह एक मजबूत और खुशहाल देश और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा परन्तु यह एक अलग-थलग राष्ट्र नहीं होगा बल्कि दूसरे देशों के साथ समान भागीदारी एवं सहयोग रखने वाला राष्ट्र होगा। जैसा कि कहावत है ''केवल शक्तिशाली हो स्वतंत्र हो सकता है और केवल उत्पादक ही शक्तिशाली हो सकता है।'' उसी नए भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं।
- 4. बहुआयामी आर्थिक चुनौतियां, जिनका हम आज सामना कर रहे हैं उस समय से अधिक प्रबल हो गई हैं जब मैंने इस सदन के सामने अंतरिम बजट प्रस्तुत 1523 GI/98 (1)

किया था। ीजहां भारत के लोगों ने 11 मई की घटना पर गौरव का अनुभव किया है वहीं विदेशों में हमारे कुछ मित्रों ने नकारात्मक रुख अपनाया है। मुझे विश्वास है कि इन प्रारंभिक नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में हमारी स्थिति को बेहतर दंग से समझते हुए नरमी का रुख आ जाएगा और इनका हमारे आर्थिक विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु हमारी नीतियां स्पष्ट रूप से विशासूचक एवं दृढ़ होनी चाहिए। गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था "जल के किनारे खड़े रहकर और उसे निहारकर आप सागर पार नहीं कर सकते।" हमारा इरादा इस सागर को पार करने का है और इस राष्ट्रीय प्रयास के लिए मैं आने वाले कुछ सप्ताहों और महीनों में इस सम्माननीय सदन का सहयोग मांगता हूं।

5. यह बजट तैयार करते समय मुझे गांधीजी के प्रसिद्ध जन्तर से मार्गदर्शन मिला है। मैंने स्वयं उस निर्धनतम और निर्बलतम व्यक्ति का चेहरा स्मरण किया है जिसे मैंने कभी देखा था और यह सुनिश्चित किया है कि यह बजट उसके लाभ के लिए हो। इस बजट की जड़ें स्वदेशी की भावना में निहित हैं और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका यह रूप स्पष्ट होता जाएगा। परंतु में यह बताना चाहूंगा कि स्वदेशी का अर्थ शेष विश्व से अलग-थलग रहने का नहीं है बल्कि स्वदेशी का अर्थ भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और इसमें सफल हो सकें। हमारे उत्साही और साहसी प्रधानमंत्री जी के शब्दों में:

लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा। कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा॥

### वर्तमान आर्थिक स्थिति

6. कुछ ही दिन पहले वर्ष 1997-98 की आर्थिक समीक्षा संसद के सभा पटल पर रखी गई थी। यह वर्ष 1997-98 के दौरान अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। मैंने अपने अंतरिम बजट भाषण में कुछ कठिनाइयों की प्रवृत्तियों की ओर ध्यान आकर्षित किया थाः वर्ष 1997-98 में समग्र आर्थिक विकास कम होकर 5 प्रतिशत रह गया था; कृषि विकास नकारात्मक था जिसमें पिछले वर्ष 199 मिलियन टन की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन घटकर 194 मिलियन टन रह गया था; औद्योगिक उत्पादन मंदी के कारण 4.2 प्रतिशत रह गया था; लगातार दूसरे वर्ष के लिए भी निर्यात निष्पादन कमजोर था और डालर के संदर्भ में षृद्धि 3 प्रतिशत से कम थी; राजकोषीय घाटे की स्थिति और बिगड़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत हो गयी थी; पूंजी बाजार की स्थिति निराशाजनक रही और आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की कठिनाइयों के कारण अर्थव्यवस्था संत्रस्त रही। परन्तु में इस स्थिति से विचलित नहीं हुआ हूं। दुर्भाग्य के शिकंजे में केवल कमजोर ही आते हैं, जो मजबूत और शिक्तशाली होते हैं वह इस पर विजय पा लेते हैं।

# मुख्य उद्देश्य

7. सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा और प्रधानमंत्री के नीति संबंधी वक्तव्यों को

ध्यान में रखते हुए में यह मानता हूं कि इस बजट के मुख्य उद्देश्य यह होने चाहिए:-

- अन्तर्निहित अनिश्चित विदेशी वातावरण का प्रभावकारी रूप से सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को सुदृढ़ करना।
- कृषि में गिरावट को दूर करके तेजी लाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
- औद्योगिक विकास, विशेषकर लघु उद्यमों की प्रगति को पुनर्स्थापित करना और पूंजी बाजार को पुनर्जीवित करना।
- आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लाना।
- इनके द्वारा तथा अन्य उपायों के द्वारा उत्पादक रोजगार अवसरों का तेजी से विस्तार करना।
- सामाजिक क्षेत्र के विकास को विशेष रूप से गतिशील बनाना।
- निर्यातों की पुनर्स्थापना और उद्यार ली गई निधियों पर निर्भरता कम करके भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को सुदृढ़, करते हुए विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की गति और प्रकृति को आंकना।
- वृहद आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति के ऊपर नियंत्रण।
- अधिक राष्ट्रीय निवेश प्राप्त करने के लिए घरेलू बचतों की दर में वृद्धि करना और इस प्रकार तीव्रतर मध्याविध विकास के लिए आधार तैयार करना, विदेशी निवेश के माध्यम से इस प्रयास को आगे बढ़ाना।
- हमारे लोगों की उत्पादक क्षमताओं को नौकरशाही की अनावश्यक खाधाओं से मुक्त करना और हमारी भूमि, श्रम और पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधार कार्य करना।

# कृषि और ग्रामीण विकास

- 8. मैं इस माननीय सदन के सामने खड़ा हूं और उसे संबोधित कर रहा हूं और ऐसा करते समय यह स्वाभाविक है कि मेरे विचार भारत के दूर-दराज के गांवों और इन गांवों के करोड़ों मेहनतकश किसानों के चारों ओर घूम रहे हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थित और उसकी गतिशीलता भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की धुरी है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए में क्या करना चाहता हूं उसका भी उल्लेख करता हूं:-
  - जल कृषि के लिए महत्वपूर्ण साधन है फिर भी विकास के इतने वर्षों के बाद भी हमारे कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 37 प्रतिशत ही आश्वस्त सिचाई के अंतर्गत है। हमारे अधिकांश निर्धन लोग वर्षा सिचित क्षेत्रों में रहते हैं। जल भेडारण सुविधा से वर्षा सिचित क्षेत्र के विकास को

उच्च प्राथमिकता प्रदान करना और उसके द्वारा निरंतर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने का हमारा प्रस्ताव है। इस समय कई मंत्रालयों और विभागों में फैले बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एकीकृत किए जाएंगे और आयोजना आवंटन, वर्ष 1997-98 में संशोधित अनुमान को 517 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 677 करोड़ रुपए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम के लिए वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रावधान में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

- ' जल के बाद अगला स्थान ग्रामीण ऋण एवं ग्रामीण आधारभूत संरचना का है। "नाबाई" द्वारा प्रबंधित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन ग्रामीण अवसंरचना विकास निधियों के अंतर्गत 7500 करोड़ रुपए की एक संचित निधि बनाई गई है जिससे 25,000 से अधिक स्कीमों के वित्तपोषण में मदद मिली है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि चौथी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के लिए आवंटन बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सुविधा का उपयोग करने के लिए में राज्यों को आगे आने का आमंत्रण देता हूं।
- मैं चालू वर्ष में "नाबाई" की शेयर पूंजी में 500 करोड़ रुपए तक की बृद्धि करना चाहता हूं। सरकार 100 करोड़ रुपए बजट से आवंटित करेगी और भारतीय रिजर्व बैंक शेष 400 करोड़ रुपए का अंशदान करेगा। इससे "नाबाई" कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकेगा।
- \* ग्रामीण बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या अत्यन्त विकट है। केवल स्व-रोजगार के जिए ही इसका निराकरण किया जा सकता है। ऐसी कोई वजह नहीं लगती कि प्रत्येक दस्तकार, कारीगर और बुनकर एक उद्यमी बन कर अपना स्वयं का छोटा कारोबार शुरु नहीं कर सके। तथापि, इसमें एक प्रमुख बाधा ऋण सुविधाओं की कमी की रही है। इससे पूर्व "नाबाई" ने लघु उद्यमियों को निधियां उपलब्ध कराने के एक माध्यम के रूप में स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को बढ़ावा देने की एक सीमित स्कीम शुरु की थी। में "नाबाई" को इस स्कीम के कार्य क्षेत्र और दायरे में काफी अधिक विस्तार करने का निर्देश दे रहा हूं ताकि लघु ऋण प्रदान करने की इस स्कीम के माध्यम से अगले पांच वर्षों में 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को मदद दी जा सके जिससे 40 लाख परिवार लाभान्वित हो सकें। 2 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाले 10000 स्वयं सहायता समूहों को इस वर्ष मदद दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक भी लघु उद्यमियों की जरुरतों को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विशेष ऋण पैकेज तैयार करने की सलाह दे रहा है।

- मैंनें राष्ट्रीय आवास बैंक से स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत गत वर्ष 50,000 इकाइयों की तुलना में इस वर्ष एक लाख ग्रामीण आवास इकाइयों को वित्तपोषित करने के लिए कहा है।
- में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के पुनर्गठन और पुनर्पूजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 265 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रबन्धन, प्रचालनात्मक और पुनर्सरचनात्मक सहायता मुहैया कराने में प्रायोजक बैंकों की भूमिका में बढ़ोत्तरी की जा रही है।
- \* किसानों को प्रायः ऐसी परिस्थितियों की वजह से जो उनके वश में नहीं हैं, ऋणों की चिरकालिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कर्जदारी के लिए उन्हें जेल की यातना तक दी जाती है। कर्ज वापसी की संस्कृति में जहां सुधार लाया जाना चाहिए, वहीं यह सरकार ऐसी स्थितियां पैदा करने के लिए कृतसंकल्प है जिससे किसी भी किसान को कर्जवापसी में चूक के लिए जेल न जाना पड़े अथवा आत्महत्या करने के लिए विवश न होना पड़े। भारतीय रिजर्व बैंक बकाया कर्जों के पुराने मामलों के समस्या रहित निस्तारण के लिए बैंकों को उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा। बैंकों को उचित मामलों में संचित ब्याज पर उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई प्रक्रिया से बैंकिंग क्षेत्र के गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की बकाया मात्रा में कमी करने में भी मदद मिलेगी।
- "नाबार्ड" से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, जिन्हें बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाया जाएगा, जारी करने की स्कीम का एक नमूना तैयार करने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि किसान उनका उपयोग बीज, खाद, कीटनाशक आदि जैसी कृषि सम्बन्धी निविष्टियों की आसानी से खरीद करने और उनकी उत्पादन की जरूरतों के लिए नकदी प्राप्त करने में कर सकें।
- 9. आज हमारी किसानों की प्रवीणता और उद्यमशीलता, कृषि उत्पादों के उत्पादन, विपणन और दुलाई से सम्बन्धित केन्द्रीय और राज्य के अनेक कानूनों से पंगु बनी हुई है। यह स्पष्टतया अस्वीकार्य है। मेरे सहयोगी कृषि राज्य मंत्री शीघ्र ही प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार की राष्ट्रीय कृषि नीति का दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो व्यापक तरीके से इन बाधाओं पर ध्यान देगी। वाणिज्य मंत्री खाद्यान्नों को छोड़कर सभी कृषि सामग्रियों के निर्यात पर मौजूदा नियंत्रणों की सुव्यवस्थित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि हमारे किसानों को व्यापक विश्व बाजारों तक अपनी पहुंच के लाभ प्राप्त नहीं हों।
- 10. हमारे देश में कृषि सहकारिता प्रणाली कई स्तरों पर नौकरशाही तथा राजनैतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त है। सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के सुगठित कार्यक्रम

के भाग के रूप में सरकार शीघ्र ही बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1904 के स्थान पर एक आदर्श सहकारी कानून लाएगी तथा राज्यों को अपने अधिनियम में इसी प्रकार का संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

- 11. लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची से कृषि उपकरणों और औजारों को अलग करने के लिए हमारे किसान आर कृषि मंत्रालय लंबी अविध से मांग करते आ रहे हैं तािक किसान प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विविध प्रकार के उपकरणों और औजारों तथा आवश्यक बिक्री के बाद की सेवा कां लाभ उठा सकें। इस प्रस्ताव की उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा भी सिफारिश की गई है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया है।
- 12. भारत ने हाल के वर्षों में तिलहनों के उत्पादन में सराहनीय प्रगित की है। एक सक्षम बाजार का माहौल कायम करने और इस क्षेत्रक में कीमतों में अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से सरकार खाद्य तिलहनों, उनके तेल और खली में भावी व्यापार शुरू करने की योजना बना रही है।
- 13. यूरिया और विनियन्त्रित फॉस्फेटी और पोटाशी उर्वरक दोनों के लिए मौजूदा सब्सिडी स्कीमों को जारी रखा जा रहा है। तथापि उर्वरक प्रयोग के बदले अधिकतम फसल की पैदावार प्राप्त करने के लिए तीनों पोपण साधकों, नाइट्रोजन (एन.) फॉस्फोरस (पी.) और पोटेशियम (के) के प्रयोग में सन्तुलन लाया जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से अन्य विनियन्त्रित उर्वरकों की तुलना में यूरिया की कम कीमत के कारण यह सन्तुलन उत्तरोत्तर बिगड़ा है। एन.पी.के. का सन्तुलन जो 1991-92 में 5.9:2.4:1 था, 1996-97 तक प्रतिकृल रूप से बदल कर 10:2.9:2 हो गया है। यूरिया के मूल्य में वृद्धि करने से इस सन्तुलन को बहाल करने में मदद मिलेगी। यह वृद्धि बढ़ती हुई लागतों के आधार पर भी औवित्यपूर्ण है, जिसकी वजह से 1995-96 और संशोधित अनुमान 1997-98 के बीच दो वर्षों में स्वदेश में निर्मित यूरिया पर सब्सिडी में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। अतः यूरिया का बिक्री मूल्य तत्काल प्रभाव से 1 रूपए प्रति किलोग्राम बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- 14. सरकार अगले पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति की एक बहुआयामी नीति अपनाई जा रही है:
  - \* त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए आवंटन 1997-98 के संशोधित अनुमान में 1302 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस नियमित बजट में 1627 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस बढ़े हुए परिव्यय से लगभग एक लाख बस्तियां लाभान्वित होंगी।
  - जैसा पहले उल्लेख किया गया है हम जल संग्रहण विकास कार्यक्रम पर विशेष बल देंगे। यह भूजल की उपलब्धता तथा संरक्षण के लिए बेहतर परिणाम भी सुनिश्चित करेगा।

- राज्यों को समुदाय-आधारित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण जलापूर्ति सुविधाओं का स्वामित्य रखने, उन्हें संचालित करने और उनका रख-रखाव करने में लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त की जाती है।
- 15. पिछले वर्षों में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों का काफी विस्तार हुआ है। प्रत्येक स्कीम के इरादे नेक थे लेकिन उनकी बहुलता से अनावश्यक देध-कार्यों, अधिक ऊपरी लागत, फील्ड स्तरों पर अव्यवस्था तथा लोगों को पर्याप्त लाभ न मिलने के परिणाम प्राप्त हुए। विभिन्न कार्यक्रमों को स्व-रोजगार स्कीम तथा मजदूरी रोजगार स्कीम की दो व्यापक श्रेणियों के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों के निधि पोषण तथा संगठनात्मक ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि इन कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

### लघु उद्योग

- 16. लघु उद्योग क्षेत्रक हमारे कुल विनिर्माण क्षेत्रक उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत, निर्यातों में 35 प्रतिशत का बहुमूल्य योगदान करता है और 160 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार देता है। लघु उद्योग क्षेत्रक के प्रति हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। लघु उद्यमियों और उनके संगठनों की सबसे आम शिकायत समय पर पर्याप्त ऋण न मिलने और "इसपेक्टर राज" के उत्पीड़न की है।
- 17. लघु उद्योग क्षेत्रक की ऋण समस्याओं पर मैं निम्नलिखित पहली का प्रस्ताव करता हूं:-
  - वर्तमान में, 2 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं वाली लघु उद्योग इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी की सीमा उनकी वार्षिक कुल बिक्री के 20 प्रतिशत के आसान परिकलन के आधार पर बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। इस सुविधा को दुगुना कर 4 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इससे लघु उद्योगों को बैंक ऋण का मिलना सुविधाजनक हो सकेगा।
  - लघु उद्योग इकाइयों को ऋण की लागत में कमी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को सलाह देगा कि पिछले अच्छे निष्पादन वाली लघु उद्योग इक इयों को मूल उधार दर पर कम लागत-अन्तर का लाभ प्रदान करें।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकांश ऋण प्रस्तावों का फैसला शाखा
     स्तर पर ही कर लिया जाय, विशिष्टीकृत लघु उद्योग शाखाओं के बैंक
     प्रबन्धकों को बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी।
  - \* इ ाय भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) भा तीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) की एक सहायक इकाई है और आई.डी.बी.आई. राज्य वित्त निगमों (एस.एफ.सी.) मै प्रमुख

शेयरधारक है। एस.आई.डी.बी.आई. को लघु उद्योगों की ऋण व्यवस्था में शीर्पस्थ भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाने के लिए, एस.आई.डी.बी.आई. को आई.डी.बी.आई. से अलग कर दिया जाएगा और राज्य वित्त निगमों में आई.डी.बी.आई. की शेयरधारिता एस.आई.डी.बी.आई. को अन्तरित की जाएगी।

- लघु उद्योग इकाइयों को प्रायः बड़ी कम्पनियों से अपनी बकाया धनराशि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण अड़चनें आती हैं। इस समस्या के निवारण के लिए में भारतीय रिजर्व बैंक से हुंडियों की भुनाई के लिए लघु उद्योगों को उपलब्ध विद्यमान व्यवस्थाओं को सुनृढ़ करने के लिए कह रहा हूं। भारतीय रिजर्व बैंक लघु उद्योग आपूर्तिकर्ता के सम्बन्ध में बड़ी इकाइयों के पास बकाया अतिदेय राशि पर अधिक जोर देने के लिए ऋण मूल्यांकन के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों को अपने दिशानिर्देशों में भी संशोधन कर रहा है। मेरे सहयोगी उद्योग मंत्री विद्यमान कानून को अधिक कारगर बनाने के लिए लघु उद्योग को विलम्बित अदायगियां और सहायक उद्योग उपक्रम अधिनियम, 1993 में अलग से संशोधन ला रहे हैं।
- 18. जहां तक "इंसपेक्टर राज" की व्यापक समस्या का सम्बन्ध है, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रशासन में दूरगामी परिवर्तनों की घोषणा करूँगा जो लघु उद्योग इकाइयों के लिए काफी मददगार होने चाहिए। लघु उद्योग इकाइयों की इंसपेक्टर राज समस्याओं का बोझ हल्का करने के लिए मैं सभी राज्यों से उनके कानूनों और विनियमों की पुनरीक्षा करने और उनमें आवश्यक परिवर्तन करने का आग्रह करता हूं।
- 19. में अपने भाषण में लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए कुछ कर रियायतों की घोषणा भी करूगा।

### उद्योग में गैर सरकारी निवेश

- 20. सरकार उद्योग में विदेशी निवेश सिहत, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमें नौकरशाही और कार्यविधि सम्बन्धी अड़चनों को कम से कम करना चाहिए और निवेशक के अनुकूल माहौल सृजित करना चाहिए। आर्थिक सुधारों के भाग के रूप में अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रकों म्रूं औद्योगिक लाइसेंसिग प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। बाकी बचे चन्द लाइसेंसशुदा क्षेत्रकों की पुनरीक्षा करने पर सरकार ने आगे कोयला और लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम उत्पादों को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय किया है।
- 21. "ईसपेक्टर राज" द्वारा थोपे गए बोझों को कम किए बिना औद्योगिक विनियन्त्रण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। अधिकांश ईसपेक्टर राज्य-स्तरीय संविधियों के तहत कार्य करते हैं। सरकार ने उद्योग से सम्बन्धित विनियामक कानूनों के समेकन की सम्भावना का पता लगाने और कम से कम बोझिल रूप में आवश्यक निरीक्षण करने में सभी राज्यों में सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के

साथ विचार-विमर्श शुरू किया है। मैं इस विषय पर अपने उत्पाद शुल्क प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय चर्चा करंगा।

22. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) ने विदेशी निवेश को बढावा देने और केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने में अच्छा कार्य किया है। विदेशी निवेश प्रवाहों में काफी अधिक वृद्धि होकर इनके 1997-98 में 3.1 बिलियन डालर होने का अनुमान है। लगभग 60 प्रतिशत निवेश स्वीकृतियां ऊर्जा और आधारभूत संरचना क्षेत्रकों में हैं। हमारा उद्देश्य ऐसी स्थितियां सृजित करना होगा जिनमें विदेशी निवेशक भारत को निवेश की एक आकर्षक मंजिल के रूप मैं पाएंगे। हम दो वर्षों के भीतर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तर्प्रवाह को दुगुना करने की आशा करते हैं। विदेशी निवेशकों को प्रायः हमारी व्यवस्थाओं और संविधियों की जानकारी की कमी और राज्य स्तर पर विशेष समस्याओं के कारण अड़चनें आती हैं। इन समस्याओं में कमी लाने के लिए हम एक ऐसी पद्धति क्रियान्वित करेंगे जिसमें प्रशासनिक मंत्रालय के एक अधिकारी को 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्येक विदेशी निवेश के प्रस्ताव के लिए केन्द्र और राज्य प्राधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना की-कार्यवाही और क्रियान्वयन में सहायता के लिए मॉनिटरिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हम एक समस्यारहित निवेश अनुमोदन कार्यविधि सुजित करने के लिए कृतसैकल्प हैं और मैं सभी विदेशी निवेशकों को आश्वस्त करना चाहंगा कि उनके निवेश प्रस्तावों पर निर्णय 90 दिन की अवधि के भीतर ले लिया जाएगा। मॉनिटरिंग अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे।

### आवास-व्यवस्था

- 23. राष्ट्रीय एजेन्डा में आवास व्यवस्था को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में रखा गया है। हम सरकार, आवासीय वित्त संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी के जिरए देश में आवासीय कमी की विशाल समस्या के समाधान की दिशा में सार्थक रूप से आगे बढ़ेंगे।
  - इस वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा
     जिनमें 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में होंगी और 7 लाख शहरी क्षेत्रों में।
  - \* इन्दिरा आवास योजना के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि कर इसे 1997-98 के संशोधित अनुमान में 1144 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस स्कीम के दायरे का भी विस्तार कर इसमें ऋण-सह-सब्सिडी कार्यक्रम को शामिल किया जा रहा है।
  - प्रयोज्य शहरी भूमि को आवासीय निर्माण के लिए मुक्त करने हेतु शहरी भूमि हदबन्दी और विनियम अधिनियम का निरसन किया जाएगा।
  - आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के पूंजी आधार को बजट से 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर बढ़ाया जा रहा है ताकि यह आवास निर्माण के लिए अधिक निधियां दे सके।

127411

\* में आधासीय व्यवस्था के लिए कुछ कर प्रोत्साहन भी देना चाहता हूं जिनका में अपने भाषण में बाद में उल्लेख करूंगा।

### आधारभूत संरचना

- 24. हमारी आधारभूत ढांचा सम्बन्धी समस्याएं जितनी विकट हैं जतना ही दृढ़ हमारा जनका समाधान करने का संकल्प है। इस बजट का एक प्रमुख आधार इन क्षेत्रकों में बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर-सरकारी निवेश के जरिए आधारभूत संरचना क्षेत्रक को पर्याप्त प्रोत्साहन देना है। इससे औद्योगिक प्रगति और समग्र आर्थिक कियाकलापों को बढ़ावा मिलने में भी मदद मिलेगी।
- 25. ऊर्जा, परिवहन और संचार के प्रमुख आधारभूत संरचना क्षेत्रकों के लिए 1997-98 के संशोधित अनुमानों में आयोजना परिव्यय 45,252 करोड़ रुपए था। मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि चालू वर्ष के लिए इन क्षेत्रकों के लिए परिव्यय 61.146 करोड़ रुपए होगा। यह 35 प्रतिशत की वृद्धि है। मुझे आशा है कि निवेशों में यह तीच्र वृद्धि औद्योगिक गतिविधि में तेजी लाएगी और आर्थिक विकास को फिर तेजी से पटरी पर लाएगी।
- 26. शासन की बागडोर संभालने के कुछ ही सप्ताह के भीतर सरकार ने बिजली दरों (टैरिफों) को युक्तिसंगत बनाने के मूल उद्देश्य से केन्द्रीय और राज्य विद्युत जिनियामक आयोगों की स्थापना करने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किया। यह विद्युत क्षेत्र में निवेशक का विश्वास बढ़ाने की दिशा में बहुत सहायक होगा और अधिक सरकारी और गैर-सरकारी निवेश के लिए संसाधन जुटाने को सुगम बनाएगा। हमने कुछ "फास्ट-ट्रेक" विद्युत परियोजनाओं, जो लम्बे समय से रुकी पड़ी थीं, के लिए सम्प्रभु काउंटर गार्रिट्या प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। हम अब इन परियोजनाओं के शीघ वित्तीय समाधान की आशा करते हैं। विद्युत मंत्रालय के लिए कुल आयोजना परिव्यय 1996-97 के संशोधित अनुमान में 6738 करोड़ रुपए और अन्तरिम बजट में 9185 करोड़ रुपए की तुलना में 9500 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- 27. पमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एन.टी.पी.सी. और कोल इंडिया पर राज्य विद्युत बोडों की बकाया देयताएं लगभग 10,000 करोड़ रुपए बनती हैं। यह भारी बकाया देयताएं सम्बधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश में गम्भीर रुकावटें हैं। सरकार ऐसी देयताओं को शामिल करने के लिए एक गार्रटी की स्कीम नैयार करेगी। इन गार्रटियों के आधार पर सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इन ऋणों की समीक्षा करके अथवा संसाधन जुटाने के लिए सीधे बाजार में प्रवेश कर संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकेंगे। इससे इन उद्यमों को विद्युत और कोयला क्षेत्रकों में विशाल परियोजनाओं हेतु निधि पोषण के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप होने वाला निवेश संयोजित प्रभावों के माध्यम से औद्योगिक विकास और निवेश को भी बढ़ावा देगा।
  - 28. हमें और अधिक सड़कों का निर्माण करना चाहिए और हमारे सड़कों की

दशा में भी सुधार होना चाहिए। हमार राष्ट्रीय राजमार्गों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। में मोजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की चार लेनों महिन नई सड़क परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रहा हूं। इस क्षेत्र के लिए कुछ और उपायों की घोषणा में अपने भाषण के भाग 'ख' में करगा।

- 29. निजी क्षेत्रक में आधारभूत सुविधा निवेश के लिये दीर्घकालिक विन यहां हेतु आधारभूत सुविधा विकास वित्त कंपनी लिमिटेड (आई.डी.एफ.सी.) को 3997 छे एक सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। मुझे सदन को मृचित करते हुए प्रसन्नता है कि आई.डी.एफ.सी. ने 1000 करोड़ रूपये की अपनी प्रतन इक्टिटी पूंजी को संयोजित कर दिया है जिसमें नो विदेशी निवेशकों की 400 करोड़ रूपए की इक्टिटी भागीदारी भी शामिल है और अब इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। राजकोषीय प्रोत्साहनों और सरकारी वित्तीय संस्थानों को दिए गए निधि जुटाने के लाभों के मामले में आई.डी.एफ.सी को दूसरे अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थानों के बराबर लाने की दृष्टि से कम्पनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का पम्लाव किया जाता है।
- 30. भविष्य निधियां निजी क्षेत्रक की आधारभूत परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करने के लिए सक्षम रूप से महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। भविष्य निधियों के लिए निर्धारित निवेश का वर्तमान स्वरूप निजी क्षेत्रक की आधारभूत परियोजनाओं की प्रतिभूतियों में किसी प्रकार के निवेश की अनुमित प्रदान नहीं करता, निजी क्षेत्रक की ऐसी प्रतिभूतियों में, जिनका कम से कम दो ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश स्वर निर्धारण किया गया हो, भविष्य निधियों की नई जमा रकमों के 10 प्रतिशत का निवेश करने की अनुमित देकर में इस संबंध में कुछ छूट का प्रस्ताव करता हूं, यह एक सक्षम उपबंध है जो इन निधियों की व्यवस्था करने वाले न्यास बोर्ड को इस बात की अनुभित देगा कि वह प्रत्येक प्रतिभूति के जोखिम प्रतिफल की संभावनाओं का अपना मूल्यांकन करके इन प्रतिभूतियों में निवेश करें।

### शिक्षा

- 31. सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण और निरक्षरता का उन्मूलन हमारी सामाजिक नीति के मूल तत्व हैं। सरकार की योजना प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए पांचवी कक्षा तक और बालिकाओं के लिए कालेज स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने हेतु साविधिक उपबन्ध को कार्यान्वित करने की भी है।
- 32. इस बजट में शिक्षा के लिए कुल बजटीय आवंटन में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है क्योंकि 1997-98 के संशोधित अनुमानों में यह आवंटन 4716 करोड़ रुपए का था और इस बजट में यह 7047 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हम चरणबद्ध तरीके से सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए कुल संसाधन आवंटन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- 33. महिला शिक्षा में तेजी लाने की एक एकीकृत योजना को सहायता देने के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना और महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत आवंटनों का एकीकरण किया जाएगा।
- 34. स्वामी विवेकानन्द ने युवकों का आह्वान करते हुए कहा था, "अपनी जाति के हित और मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को बिलदान करना एक महान कार्य है।" युवकों की असीमित शक्ति का उपयोग करने के लिए सरकार राष्ट्रीय एजेंडा में की गयी वचनबद्धता को बनाए रखने हेतु एक राष्ट्रीय पुनर्गठन कोर के सृजन की एक स्कीम तैयार करेगी जो सामुदायिक आधार पर राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों के लिए युवकों को तैयार करेगी। यह स्कीम युवकों के स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी जिसके द्वारा स्वरोजगार वाले व्यवसायों को चलाने के लिए स्वयंसेवकों को इसके साथ ही साथ व्यवसायों और उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके ब्योर तैयार करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी समिति गठित की जा रही है।

### सूचना प्रौद्योगिकी

- 35. प्रधानमंत्री ने भारत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अत्यधिक महत्व पर जोर दिया है. यह विश्व अर्थव्यवस्था की तरह वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रक है। रोजगार उत्पन्न करने, आय और निर्यात आमदनी के लिए इसकी अपार क्षमता है। महिलाओं के लिए यह करोड़ों कुशल रोजगार भी प्रदान कर सकता है। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और साफ्टवेयर निर्माता विश्व में किसी से कम नहीं हैं।
- 36. सरकार ने दस वर्षों के अंदर भारत को एक विश्व सूचना प्रौद्योगिकी शक्ति बनाने और साफ्टवेयर के सबसे बड़े उत्पादक एवं निर्यातक के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक राष्ट्रीय आसूचना नीति तैयार करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल का गठन कर दिया गया है जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- 37. हमारी साफ्टवेयर कम्पनियां विशव बाजार में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्य करती हैं और इन कम्पनियों में कार्य कर रहे कुशल व्यावसायिकों को विदेश में आकर्षक अवसर उपलब्ध हैं। अपने मानव संसाधनों को बनाए रखने के लिए हमारी कम्पनियों को लचीली प्रोत्साहन प्रणालियां तैयार करने की जरुरत है। उन्होंने विदेश में ए.डी.आर/जी.डी.आर. से सम्बद्ध अपने भारतीय कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प स्कीम प्रदान करने के लिए अनुमित मांगी है जिसके अन्तर्गत उनके कर्मचारी ए.डी.आर/जी.डी.आर स्टॉक विकल्प के पात्र होंगे। इस क्षेत्रक में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य और इसकी अति विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सॉफ्टवेयर क्षेत्रक हेतु ऐसे विकल्पों की अनुमित के लिए एक विशेष स्कीम तैयार करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के विवरणों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- 38. इस महत्वपूर्ण क्षेत्रक के तीव विकास को सहायता देने के लिए मेरे पास कुछ राजकोषीय प्रस्ताव भी हैं जिन्हें मैं बाद में अपने भाषण में प्रस्तुत करुंगा।

### वित्तीय क्षेत्रक

- 39. बचतों को प्रोत्साहन देने, निवेश को अति उत्पादक कार्यकलापों की दिशा में लगाने और एक कारगर भुगतान प्रणाली सुनिष्चित करने के लिए एक सुविकसित एवं अच्छी तरह से कार्य कर रही विसीय प्रणाली अनिवार्य है। पूर्वी एशिया के विसीय संकट ने हमारी विसीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तुरन्त कार्रवाई के महत्व को उजागर किया है। हाल ही में प्रस्तुत नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें दी गई हैं जिनकी भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करते हुए जांच की जा रही है। तथापि, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निर्णय लिए गए हैं।
  - \* हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का अपेक्षतया उच्च स्तर चिन्ता का विषय है। निवल गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां जो 1996-97 में औसतन 9 प्रतिशत थीं उन्हें वर्ष 2000-2001 तक 5 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाया जाना चाहिए। गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) को कम करने के एक उपाय के रूप में ऋण-वसूली न्यायाधिकरणों को सुदृढ़ किया जाएगा और सभी राज्यों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए अधिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे।
  - \* कुछ बैंकों में एन.पी.ए. विशेष रूप से अधिक हैं। एक परीक्षण के आधार पर इन बैंकों को परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो उनके वसूली योग्य मूल्य पर बैंकों के एन.पी.ए. को अपने नियंत्रण में लेंगे और बैंकों द्वारा धारण किए जाने वाले विशेष बांडों के साथ अदला-बदली करेगी। परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां उन्हें हस्तान्तरित परिसम्पतियों के लिए अधिकतम मूल्य वसूल करने हेतु बकाया धनराशि की वसूलियों पर ध्यान केन्द्रित करेगी।
  - हमारे बैंकों के गिरते हुए स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2000 तक वर्तमान 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत और इसके बाद यथाशीग्र 10 प्रतिशत कर रहा है। परिसम्पत्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण, जोखिम भार आदि के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण मानदंडों की कुछ अन्य वृद्धियों की भारतीय रिजर्व बैंक घोषणा भी करेगा।
  - मम्पत्तियों एवं वित्तीय दस्तावेजों के हस्तान्तरण एवं लेन-देनों के सम्बन्ध में हमारी वित्तीय प्रणाली आज अनेक पुराने कानूनों के बोझ के नीचे कार्य कर रही है। मुख्य कानूनों में सुस्पष्ट कानूनी संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जा रहा है ताकि इनके उपबंधों को आधुनिक वित्तीय एवं वैंकिंग पद्धतियों के अनुरूप बनाया जा सके।
  - 40. गैर-बैंक वित्त कम्पनियां (एन.बी.एफ.सी.) हमारे वित्तीय क्षेत्रक में एक

महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं परन्तु असावधान एवं सीधे-सादे छोटे निवेशकों के सं रक्षण के लिए इस क्षेत्रक में विनियमों को सुधारना होगा। एन.बी.एफ.सी के सुधरे हुए विनियमन के लिए एक आधार संरचना निर्धारित करने की दृष्टि से पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने एन.बी.एफ.सी के पंजीकरण और उनके लिए प्रभावकारी विनियमन के लिए हाल ही में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। हमारा उद्देश्य विवेकपूर्ण विनियमनों और पर्यवेक्षी प्रणाली की एक आधार संरचना विकसित करना होगा जो स्वस्थ वित्तीय प्रणाली का विकास करेगी और पारदर्शी प्रकटीकरण मानदंद भी प्रदान करेगी जिससे निवेशकों द्वारा अच्छी जानकारी पूर्ण निवेश निर्णय लेने के लिए जमाकर्ताओं में अधिक जागृति पैदा होगी।

41. बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के साथ-साथ बीमा क्षेत्र में भी सुधार की ओर आगे बढ़ना आवश्यक है। इस क्षेत्र में अब तक सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार रहा है। हमारे नागरिकों को बेहतर बीमा कवच उपलब्ध कराने और आधारभूत संरचना के विस्तापिण हेतु, दीर्घकालिक संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए मैं बीमा क्षेत्र को भारतीय निजी कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता के लिए खोलने का प्रस्ताव करता हूं। बीमा विनियामक प्राधिकरण को सांविधिक निकाय में बदला जाएगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान इस वर्ष बाद में लाया जाएगा।

### 'फेमा' और काले धन का वैधीकरण

- 42. वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) पुराना हो चुका है और अर्थव्यवस्था की जरुरतों एवं विदेशी मुद्रा बाजारों एवं लेन-देनों में घटित परिवर्तनों के अब यह अनुरूप नहीं रहा है। हम पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब यह उचित नहीं रहा कि हम विदेशी मुद्रा की एक विशेष शिक्त के रूप में पूजा करें और इस शिक्त के चारों ओर एक बोझिल एवं उच्च विनियमनात्मक संरचना खड़ी करें। तदनुसार सरकार ने 'फेरा' को निरस्त करने और उसके स्थान पर एक नया विदेशी मुद्रा-प्रबंध अधिनियम (फेमा) लाने की निर्णय लिया है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। यह नया विधेयक संसद के इस सन्न में पेश किया जाएगा।
- 43. इसके साथ ही साथ में सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 'फेरा' के स्थान पर 'फेमा' लाने का प्रयोजन नशीली दवाओं के विक्रेताओं, आतंकवादियों, हथियार तस्करों और दूसरे जघन्य आर्थिक अपराध करने वालों के गैर-कानूनी लेन देन, को लाइसेंस देना कदापि नहीं है। वास्तव में काले धन के वैधीकरण की बढ़ती हुई विश्व-व्यापी समस्या से अपने समाज को बचाना हमारा उद्देश्य है और मैं 'फेमा' के साथ ही काले धन का वैधीकरण निवारण विधेयक सदन के सामने पेश करगा।

### पूजी-बाजार

- 44. हमारे पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करने के लिये मैं अनेक उपायों का प्रस्ताव कर रहा है।
  - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार में अधिक नकदी की

सुरक्षा एवं प्रवाह के लिये अधिक अवसर प्रदान करने के उपाय के रूप में "स्टाक इंडेक्स फ्यूचर्स" में व्यापार शुरु करने का अनुमोदन कर दिया है। सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम में आवश्यक संशोधन लायेगी ताकि व्युत्पन्न विलेखों को प्रतिभूतियों के रूप में माना जा सके।

- आज विदेशी संस्थागत निवेशको (एफ.आई.आई.) की ऋण निधियों को केवल सूचीकृत ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमित है। मैं उन्हें असूचीकृत घरेलू ऋण प्रतिभूतियों में भी निवेश करने की अनुमित का प्रस्ताव करता हूं। चूक के मामले में जोखिम विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा वहन किया जाएगा।
- दलालों की सेवाओं के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी अनुलाभ कर लगाये खिना अपने कारोबार के निगमीकरण के लिये भेयर दलालों को गत वर्ष एक बार की अनुमति दी गई थी । मैं इस छूट को एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
- और अधिक सरकारी निर्गमों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं सरकारी निर्गमों पर किये गए व्ययों की आय कर कटौती के विस्तार के लिए कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रहा हूं।
- हाल के वर्षों में शेयर बाजारों में कुछ असतीयजनक घटनाओं के बाद छोटे निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए एक विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। दलालों एवं दूसरे बाजार के बिचौलियों की चूकों और वित्तीय असफलताओं से छोटे निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु विशेष ध्यान देने के लिए में "सेबी" से कह रहा हूं।

# अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.)

- 45. भारत से बाहर मैंने जहां भी यात्रा की है, अनिवासी भारतीयों ने भारत के विकास में सार्थक योगदान करने की हार्दिक इच्छा व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि अनिवासी भारतीय भारत के विकास के लिए एक महान, उपयोग में न लाई गई क्षमता रखते हैं। अपने मूल देश के विकास में भाग लेने के लिए मैं अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूं:
  - प्रतिशत अनिवासी भारतीय के लिए कंपनी की कुल इक्विटी के 1 प्रतिशत और एन.आर.आई. विदेशी कंपनी निकाय के लिए कंपनी में कुल एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेशों के लिए 5 प्रतिशत की सीमा की शर्त पर दितीयक बाजार में भारतीय कंपनियों में शेयर खरीदने के लिए इस समय एन.आर.आई. को स्वीकृति है। यह सीमाएं बहुत वर्ष पहले तब लगाई गई थीं जब हमारे पूंजी बाजार विनियम काफी कमजोर थे और अधिग्रहणों एवं अधिकार में लेने को शासित करने वाले कोई नियम नहीं

- थे। यह स्थिति इन दोनों के मामले में मूर्त रूप से बदन चुकी है। अतः में एन.आर.आई. के मामले में यह व्यक्तिगत निवेश सीमा 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने और कंपनी में सभी एन.आर.आई. निवेशों के लिए 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।
- \* एन.आर.आई. ने मुझसे यह भी शिकायत की है कि हमारे शेयर बाजारों में उनकी भागीदारी को शासित करने वाली प्रक्रियायें अत्यधिक बोझिल एवं भारी हैं। मैं इन प्रक्रियाओं की पूर्ण रूप से पुनरीक्षा कर रहा हूं ताकि हमारे शेयर बाजारों में एन.आर.आई. द्वारा निवेश को सुविधापूर्ण बनाने के लिए संशोधित किया जा सके।
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक "न्यू इंडिया मिलेनियम स्कीम" आरंभ करेगा जो केवल एन.आर.आई. हारा डालरों में अंशदान के लिए खुली होगी। इस स्कीम के अंतर्गत संग्रहीत धन का भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाएगा जिसकी वृद्धि की काफी क्षमता होगी और अच्छे किस्म के भारतीय ऋण की सुविधा होगी। इस स्कीम के ब्योरों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।
- भारतीय स्टेट बैंक एन.आर.आई. द्वारा अंशदान के लिए विदेशी मुद्राओं के मूल्य में एक नया "रिसरजेंट इंडिया बाण्ड" शुरू कर रहा है । इससे अनिवासी भारतीयों को हमारे देश के विकास विशेषकर आधारभूत संरचना निर्माण के लिए संसाधनों की प्राप्त में योगदान करने में मदद मिलेगी । यह बाण्ड पूर्ण रूप से स्वदेश लौटाने योग्य होंगे और सरकार इन नए बाण्डों के लिए वही रियायतें देगी जो एन.आर.आई. जमा राशियों पर इस समय उपलब्ध हैं । इस स्कीम के ब्यौरे अलग से अधिसूचित किए जाएंगे । मुझे विश्वास है कि हमारे अनिवासी भारतीय भाई इस पहल का स्वागत करेंगे और इन बाण्डों में उदारतापूर्वक योगदान करेंगे।
- 46. मुझे अनिवासी भारतीयों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। सरकार ने विदेश में रहने वाले और विदेशी पासपीर्ट रखने वालों के लिए भारतीय मूल का व्यक्ति (पी.आई.ओ.) काई जारी करने की एक स्कीम तैयार करने का निर्णय लिया है। पी.आई.ओ. काई, जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले देशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे, वीजा-मुक्त प्रणाली शुरु करने के अतिरिक्त कुछ विशेष आर्थिक, शैक्षणिक, वित्तीय और सांस्कृतिक लाभ भी प्रदान करेंगे। इसके क्योर तैयार किए जा रहे हैं।

# विकेन्द्रीकरण और व्यय पुनर्सरंचना

47. राज्यों को अतिरिक्त विसीय शक्तियां प्रदान करने और राज्यों द्वारा अधिक संसाधन जुटाने के लिए अतिरिक्त या वैकल्पिक उपायों की जांच एवं उनकी सिफारिश हेतु श्री भैरों सिंह शेखावत की अध्यक्षता में सरकार ने पहले ही राज्यों को शक्तियों के हस्तान्तरण से संबंधित एक विशेषक कार्य दल की नियुक्ति कर दी है। कार्य दल

की पहली रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। हम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके इन सिफारिशों की जांच कर रहे हैं।

- 48. हमारी बजट प्रणाली में आयोजना एवं आयोजना-भिन्न व्ययों के बीच अन्तर ने अनेक समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं। इसके कारण तथाकथित आयोजना व्ययों पर जितना अधिक ध्यान केन्द्रित होता है उतनी ही उपेक्षा अनुरक्षण जैसी मदों की होती है, जिन्हें आयोजना-भिन्न के रूप में रखा गया है। वित्त आयोग जैसे विभिन्न निकायों ने बजट में आयोजना और आयोजना-भिन्न के अंतर को समाप्त करने की पैरवी की है। में इन मुद्दों की व्यापक तरीके से जांच करने और बजट में सरकारी व्यय को कार्यात्मक रूप से सभाव्य एवं अधिक एकाग्र तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सिफारिशें करने हेतु एक कार्य दल के गठन का पस्ताव करता हूं जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य सरकारां के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- 49. एक संबंधित समस्या इन वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्रक एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की बहुलता की रही है। परस्पर-व्याप्ति एवं द्वेध कार्यों को कम करने, प्रक्रियाओं एवं मानदण्डों के संशोधन और लक्षित लाभार्थियों की इन तक आसानी से पहुंच के उद्शय से इन्हें युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है। उपर्युक्त कार्यदल इस विषय पर भी सलाह देगा।

# पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

- 50. सरकार ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आधारभूत कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के पुनर्गठन का पहले ही निर्णय ने लिया है। सिक्किम को भी इस परिषद में शामिल किया जाएगा। इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए संसद में आवश्यक विधान पेश किया जाएगा।
- 51. इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मंत्रालयों से निधियां जमा करने के लिए एक कालातीत न होने वाला केन्द्रीय संसाधन पूल बनाया जाएगा जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आयोजना व्यय मंत्रालय के कुल आयोजना आवटन के 10 प्रतिशत से कम है। आवंटन के 10 प्रतिशत और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर हुए बास्तविक व्यय के बीच के अन्तर को केन्द्रीय पूल में अन्तरित कर दिया जाएगा, जिसका उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के विशिष्ट कार्यक्रमों के निधिपोषण के लिए किया जाएगा।
- 52. सरकारी क्षेत्रक के वित्तीय संस्थानों एवं वैंकों द्वारा समर्थित पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (एनईडीएफसी) को 1995 में निगमित किया गया था। एनईडीएफसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कार्य करता है। इस समय असम में एक राज्य वित्त निगम और कुछ दूसरे राज्यों में दोहरे कार्य करने वाले औद्योगिक विकास निगम हैं। इन संस्थानों के स्वस्थ एवं कुशल विकास के लिए में यह प्रस्ताव करता हूं कि आगे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य वित्त निगमों/औद्योगिक विकास

निगमों के औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त कार्य आईडीबीआई/सिडवी' के बजाय अब एनईडीएफसी द्वारा किया जाएगा।

# विनिवेश/निजीकरण/सरकारी क्षेत्र के उद्यम से सम्बद्ध सुधार

- 53. नियमित बजट को चालू वर्ष में विनिवेश से 5000 करोड़ रुपए की प्राप्ति का श्रेय जाता है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सरकार ने आई.ओ.सी. 'गेल', वी.एस.एन.एल. और 'कॉनकोर' से इक्विटी के विनिर्दिष्ट भाग का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। इंडियन एयरलाइंस की पुनर्सरचना करने की समग्र नीति के रूप में और इसकी क्षमता में विस्तार के लिए सरकार ने इंडियन एयरलाइंस की पूंजी को पुनर्गठित करने और साथ ही इस कम्पनी में तीन वर्षों में चरणबद्ध विनिवेश करने और सरकार की इक्विटी धारिता 49 प्रतिशत तक नीचे लाने का निर्णय लिया है।
- 54. जुध सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निरन्तर भारी घाटे में चल रहे हैं। स्वतंत्र संगठनों द्वारा किए गए अनुभव और अध्ययनों ने अन्ततः उन्हें पुनरुज्जीवित करने योग्य नहीं पाया है, तथापि, केवल कामगारों के हितों की चिन्ता के कारण उनको बन्द करने सम्बन्धी निर्णय लेने में देर हुई। इस ऊहापीह का व्यवहार्य और सन्तोषजनक समाधान करने के लिए, सरकार ने बन्द होने के कगार पर खड़े उद्यमों के कामगारों के लिए उन उद्यमों को बन्ट करने से पहले उदार और आकर्षक प्रतिपृति पैकेज प्रदान करके . उन्हें सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, जब कोई इकाई बन्द होती है तो उसमें कार्यरत कामगार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत केवल छंटनी के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं, जो सेया के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में केवल 15 दिन की मजदूरी के बराबर है। इस प्रतिपूर्ति पैकेज को आकर्षक अनाने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के लाभों को लाग् करने का प्रस्ताव है, अर्थात सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दिवसों की मजदूरी प्रदान की जाएगी जो इन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के बन्द होने के समय सभी कामगारों के सम्बन्ध में उनके वकाया सेवा वर्षों के आधार पर अधिकतम मजदूरी अथवा सीचत वेतन के अधीन होगी। पैकेज में और सुधार के रूप में इन इकाइयों के कामगार यदि उन्होंने अधिकतम 30 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है तो वे अधिकतम 60 महीनों अथवा 5 वर्ष का वेसन अथवा मजद्री प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसका तात्पर्य यह होगा कि वे सभी कामगार जिन्होंने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है, वे सामान्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की अपेक्षा अधिक राशि प्राप्त करेंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की अन्य शर्तें भी लागू होंगी और यह पेशकश समयबद्ध होगी।
  - 55. इस उद्देश्य के लिए बजट में एक पृथक पुनर्सरिवित निधि तैयार की जा रही है और इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कामगारों को प्रतिपूर्ति पैकेज का भुगतान करने के लिए इजट से अग्रिम तौर पर निधि उपलब्ध करायी जाएगी। एक बार श्रिमकों के उद्यम से अलग हो जाने पर कम्पनी की परिसम्पत्ति सर्वोत्तम किफायती मूल्य पर निपटान हेतु उपलब्ध हो जाएगी। सभी बकाया देयताओं का निपटान करने

के बाद, निपटान से प्राप्त आय को पुनर्गिठत निधि में डाल दिया जाएगा और उसी सीमा तक इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे निधि को कम से कम आंशिक रूप से आत्मनिर्भर आधार पर संचालित करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में निधि से बजटीय सहायता में क्रमिक कभी आएगी।

56. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सामान्य रूप से इन मामलों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता कम करके 26 प्रतिशत की जाए। महत्वपूर्ण उद्यमों के मामले में सरकार अधिकांश धारिताओं को बनाए रखेगी। सभी मामलों में कामगारों के हितों को सरक्षण दिया जाएगा।

# वर्ष 1998-99 के लिए बजट अनुमान

- 57. जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों के ब्यौरे अन्तरिम बजट के साथ मार्च, 1998 में प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए में उन अनुमानों के सम्बन्ध में पुनः चर्चा नहीं कर रहा हूं। नीचे जो आंकड़े दिए गए हैं, वे वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान हैं। में उनकी वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों के साथ तुलना करूंगा क्योंकि बजट अनुमान अंततः अनुमान ही होते हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वह पूर्व वर्ष में किए गए व्यय और इस वर्ष के बजट में प्रस्तावित वृद्धि से सम्बद्ध है।
  - 58. अब मै संक्षेप में वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों की तरफ आता हूं।
- 59. वर्ष 1998-99 के लिए, कुल व्यय का अनुमान 2,68,107 करोड़ रुपए लगाया गया था। 'इसमें से 72,002 करोड़ रुपए केन्द्रीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के सम्बन्ध में बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं और शेष 1,96,105 करोड़ रुपए की राशि आयोजना-भिन्न व्यय के लिए हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि आयोजना के लिए बजट सहायता 1997-98 के संशोधित अनुमानों में मौजूद 60,630 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,372 करोड़ रुपए हो गयी है जो अब तक सभी प्रकार से सर्वाधिक बढ़ोतरी है। यहां तक कि प्रतिशवता के रूप में 18.8 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी एक वर्ष को छोड़कर पिछले दशकों में सबसे ज्यादा रही।

# आयोजना व्यय

### केन्द्रीय आयोजना

60. 1,05,187 करोड़ रुपए का कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय पिछले वर्ष के 81,033 करोड़ रुपए के स्तर की तुलना में 24,154 करोड़ रुपए अधिक होगा। केन्द्रीय आयोजना से सम्बद्ध सकल बजटीय सहायता को 1997-98 के संशोधित अनुमानों में 33,629 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 42,464 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस बकाया राशि की पूर्ति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी। केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए की गयी 5,741 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है।

- 61. आयोजना आवंटन हमारी प्रमुख प्राथिमकताओं को प्रदर्शित करता है। कृषि मैत्रालय के लिए आयोजना आवंटन में 58 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 1807 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2854 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- 62. वर्ष 1998-99 के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मैत्रालय के लिए आयोजना आवंटन की राशि बढ़ाकर 9912 करोड़ रुपए की जा रही है जो वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की 8356 करोड़ रुपए की राशि में 1556 करोड़ रुपए की वृद्धि है।
- 63. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन राशि बढ़ाकर 3684 करोड़ रुपए है जो वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान 2747 करोड़ रुपए की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि है।
- 64. शिक्षा विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि 3351 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4245 करोड़ रुपए कर दी गई है।
- 65. कल्याण मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन की 804 करोड़ रुपए की राशि में 91 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 1539 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के लिए 92 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए 41 करोड़ रुपए, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के शेयर पूंजी अंशदान के लिए 60 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए 28 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास और विज निगम के लिए 10 करोड़ रुपए की राशियां शामिल है।
- 66. वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की हमारी खोज बनाए रखने के लिए परभाणु ऊर्जा विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि में 68 प्रतिशत की वृद्धि करके 828 करोड़ रुपए से 1391 करोड़ रुपए की जा रही है और अंतरिक्ष जिभाग के लिए आयोजना आवंटन में 62 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 850 करोड़ रुपए से 1381 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- 67. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोती की क्षमता का पता लगाने के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत संत्रालय का आयोजना आवंटन 190 करोड़ रुपए से दुगुने से अधिक बढ़ाकर 404 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- 68. पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन की 440 करोड़ रुपए की राशि भें 60 प्रतिशत चृद्धि करके जसे 704 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- 69. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के लिए बजटीय समर्थन 122 करोड़ रुपए के तिगुने से भी अधिक बढ़ाकर 379 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- 70. महिला और बाल विकास विभाग के लिए आयोजना आवेटन 1026 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1226 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

# राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

71. में संशोधित अनुमान, 1997-98 में 27001 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में केन्द्रीय आयोजना सहायता के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 28538 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूं। राज्य की आयोजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 12888 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15037 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। जनजातीय उप-आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 330 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 380 करोड़ रुपए की जानी प्रस्तावित है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि 5000 करोड़ रुपए रखी गई है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और गंदी बस्ती के विकास की स्कीमों के लिए सहायता राशि 2873 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3760 करोड़ रुपए की जानी प्रस्तावित है।

### नई स्कीमें

- 72. 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था सिंहत गैर-ऋणी किसानों को शामिल करने के लिए 24 चुनिंदा जिलों में एक नई प्रायोगिक फसल बीमा स्कीम शुरू की जा रही है।
  - 73. 60 करोड़ रूपए की व्यवस्था सहित कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन की एक नई स्कीय शुरू की जा रही है।
  - 74. 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था महित राष्ट्रीय उद्यानों और परियोजना क्षेत्रों से विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास की एक नई स्कीम शुरू की जा रही है।

### आयोजना-भिन्न व्यय

- 75. वर्ष 1998-99 में कुल आयोजना-भिन्न व्यय वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 174615 करोड़ रुपए की तुलना में 196105 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।
- 76. ब्याज भुगतानों के लिए प्रावधान वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 65700 करोड़ रुपए से बढ़कर 75000 करोड़ रुपए हो गया है।
- 77. रक्षा व्यय के लिए प्रावधान वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 36099 करोड़ रुपए से काफी बढ़कर 41,200 करोड़ रुपए हो गया है। मैं अगर आवश्यक हुआ तो वर्ष के दौरान बजटीय समर्थन में वृद्धि करने पर विचार करूंगा। हमारी रक्षा संबंधी तैयारियों से कोई समझौता नहीं हो सकता।
- 78. वर्ष 1998-99 में खाद्य सब्सिडी के लिए 9000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जा रही है, जो वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की तुलना में 1500 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदर्शित करती है। चीनी के लिए सब्सिडी हेतु प्रावधान 400 करोड़ रुपए रखा गया है। गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल के संशोधन और पिछले वर्षों से संबंधित बकायों के निपटान करने के कारण भी खाद्य सब्सिडी में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

- 79. यूरिया के बिक्री मूल्य में परिवर्तन के अनुसरण में देशी नाइट्रोजनी उर्वरकों पर सब्सिडी वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की 6600 करोड़ रुपए की राशि से घटाकर 6000 करोड़ रुपए की जा रही है। विनियंत्रित फॉस्फेटी और पोटाशी उर्वरकों पर सब्सिडी वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 2600 करोड़ रुपए की राशि से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए की जा रही है।
- 80. वर्ष 1998-99 में राज्यों की अनुदान की राशि वर्ष 1997-98 के सं शोधित अनुमान में 4114 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6314 करोड़ रुपए की जा रही है, जो 2200 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदर्शित करती है। इसमें से 950 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदर्शित करती है। इसमें से 950 करोड़ रुपए की वृद्धि विश्वविद्यालय और कॉलेज़ के शिक्षकों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए राज्यों को सहायता देने के कारण हुई है। शेष वृद्धि मुख्यतः दसवें विस्त आयोग की सिफारिश के अधीन अनुदान के कारण है।
- 81. पेंगन के लिए प्रावधान वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 459 करोड़ रुपए बढ़ाकर 7342 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह व्यवस्था करते समय सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के सरकारी निर्णय के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है। इसका अल्प बचत संग्रहणों पर भी प्रभाव पड़ेगा। निवल अल्प बचतों के संग्रहण की एवज में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों का प्रावधान 1997-98 के संशोधित अनुमानों में 15732 करोड़ रुपए की तुलना में 14,200 करोड़ रुपए रखा जा रहा है।
- 82. मुख्यतः रुग्ण और स्थिति सुधार रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण हेत् 1482 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

# राजस्व प्राप्तिया

- 83. मैं अब राजस्व प्राप्तियों की चर्चा करुंगा।
- 84. माननीय सदस्यगण को अवगत है कि दिनांक 17 जुलाई, 1997 को आयोजित अंतर्राज्यीय परिषद की तीसरी बैठक में हुई आम सहमित के आधार पर तत्कालीन सरकार ने केन्द्र के कर राजस्वों में राज्यों की हिस्सेदारी की वैकल्पिक स्कीम में संबंधित दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने का सिद्धांततः अनुमोदन कर दिया था। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमने इस निर्णय को अनुसमर्थन दिया है। तदनुसार, में केवल एक संशोधन के साथ इस वैकल्पिक स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए शीघ्र ही एक संविधान संशोधन विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करता हूं। संशोधन यह है कि केन्द्रीय करों की सकल प्राप्ति में राज्यों की प्रतिशत हिस्सेदारी की पुनरीक्षा परवर्ती वित्त आयोग द्वारा की जाए न कि इसे 15 वर्षों के लिए रोक दिया जाए जैसांकि दसवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है।
- 85. कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व 148506 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। जैसाकि माननीय सदस्यगण अवगत हैं, हमने स्वैच्छिक आय

प्रकटीकरण स्कीम, 1997 की आय में राज्यों के हिस्से के लिए 1997-98 के संशोधित अनुमान में 7594 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 1998 तक 10050 करोड़ रुपए का संग्रहण अनुमानित था। तथापि, वास्तविक संग्रहण लगभग 1000 करोड़ रुपए कम हुआ है। राज्यों को अदा किए गए अधिक हिस्से के लिए समायोजन करने के बाद में राज्यों को करों के हिस्से के रूप में 39074 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूं। इस प्रकार वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 99158 करोड़ रुपए की तुलना में केन्द्र का निवल कर राजस्व 109432 करोड़ रुपए होगा। कर-भिन्न राजस्व का वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 39356 करोड़ रुपए से बढ़कर इस वर्ष 45137 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। मैंने सेलूलर और बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के आपरेटरों से लाइसेंस फीस के रूप में 2800 करोड़ रुपए और भारतीय रिजर्व बैंक के निवल अधिशेष लाभ के रूप में 4200 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

- 86. कर-भिन्न प्राप्तियों सिहत केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमान में 138514 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 154569 करोड़ रुपए होने की आशा 🕷
- 87. पूजी प्राप्तियों के क्षेत्र में बाजार उधार की राशि 55931 करोड़ रुपए आंकी गई है। निवल विदेशी सहायता 2337 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से 5000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का श्रेय ले रहा हूं।
  - 88. मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में राजकोषीय घाटे की चर्चा करूंगा।
  - 89. महोदय, अब मैं अपने कर प्रस्तावों पर आता हूं।
  - 90. कठोर बजट की बहुत बातें हुई हैं। वर्तमान स्थित में करों में वृद्धि करने का अत्यधिक प्रलोभन था। परंतु में मानता हूं कि प्रत्यक्ष कर नीति में स्थायित्व हो और यह व्यक्तियों और कंपनियों दोनों को विश्वास प्रदान करें। अतएव, इस संबंध में किसी भी अनिश्चितता को समाप्त किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष लागू की गई कर दरें काफी संतुलित हैं। व्यक्ति कर या कंपनी कर किसी भी कर ढांचे में वोई परिवर्तन लागू करने का मेरा प्रस्ताव नहीं है। में आशा करता हूं कि कर ढांचे में दीर्घावधिक स्थायित्व वढ़ी हुई उत्पादकता, स्वैच्छिक कर अनुपालन का एक अच्छा परिवेश सृजित करेगा और कर के दायर का विस्तार करने के हमारे प्रयासों में वृद्धि करेगा। वास्तव में, मैं कुछ रियायतों की घोषणा करने जा रहा हूं। सीमांत स्तर पर कर दाताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए, कर संबंधी छूट का स्तर 40,000 रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा रहा है।
  - 91. वेतनभोगी, जिनकी आय 1 लाख रुपए तक है, को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं उनके मामले में मानक कटौती की उच्चतम सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि उनकी प्रसन्नता में 5 लाख रुपए से अधिक की आय वाले वेतनभोगी भी शामिल हाँगे क्योंकि इसके वाद इस कटौती के वे हकदार नहीं होंगे। वेतनभोगी, जिनकी आय 1 लाख रुपए और

5 लाख रुपए के बीच है, के लिए वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। मैं चिकित्सा व्यय की कर-मुक्त प्रतिपूर्ति की उच्चतम सीमा को भी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

- हमारे जैसे विशाल देश में यह अत्यधिक चिंता की बात है कि कर 92. निर्धारितियों की कुल संख्या हमारी आबादी के 1.25 प्रतिशत से भी कम है। कर आधार का विस्तार करने की गुंजाइश प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में एकमात्र बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह कराधान नीति का सुस्वीकृत सिद्धांत है कि करों की संयत दरें तभी अर्थ रखती हैं जब कर जाल व्यापक हो और कर अपवंचन की गुंजाइश को उत्तरोतर कम किया जाए। इस उद्देश्य के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण पहल करने का प्रस्ताय करता हूं। पिछले वर्ष 12 महत्वपूर्ण शहरों में जहां आप चार मानदण्डों में से कोई दो पूरा करते हों जैसे आप घर के स्वामी हों, टेलीफोन रखते हों, विदेश यात्रा पर खर्च कर रहे हों और मोटर गाडी के मालिक हों तो आपको आयकर विवरणी दाखिल करनी होगी, ऐसी एक स्कीम आरंभ की गई थी। इस स्कीम में कई खामियां थीं, जिसे में हटाने का प्रस्ताव करता है। सर्वप्रथम, इस स्कीम का अब भारतें के 23 और शहरों को शामिल करने के लिए विस्तार किया जा रहा है, जिसमे कुल 35 शहर इसमें शामिल हो जाएंगे। कर जाल को दो अतिरिक्त मानदण्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड रखना और महंगे क्लवी की सदस्यता शामिल करने के लिए बढाया जा रहा है, जिससे कुल पैरामीटर छ हो जाएंगे। अंततः चार पैरामीटरों में से दो को मिलाना प्रशासनिक रूप से एक दूभर कार्य होने के अतिरिक्त कई संभावित कर निर्धारितियों के लिये बचाव का मार्ग भी प्रदान करता है। मैं विश्वास करता है कि यदि कोई व्यक्ति इन छः मानदण्डों में से एक की पूर्ति करता है तो उससे आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए कहना उचित होगा। इसके बाद यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या वह कर का भुगतान करने योग्य है अथवा नहीं। यह संशोधित स्कीम अब "छ: में एक", नाम से ज्ञात होगी, और हमारे कर आधार को विस्तृत बनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। मेरा अभिप्राय पूर्ण राजकोषीय वर्ष के दौरान अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करना है।
- 93. कर आधार को विस्तृत करने के कार्य के अलावा कर-अपवंचन एक गंभीर बाधा बनी हुई है। जहां लागू कराने संबंधी प्रयासों को सुदृढ़ किया जाएगा, वहां में कितिपय उच्च मूल्य के लेन-देनों के संबंध में निर्धारितियों के लिए अपनी "पैन" अथवा "जीआईआर" संख्या बताना अनिवार्य करने के लिए एक नई पहल करने का प्रस्ताव करता हूं। ये लेन-देन निम्नलिखित होंगे:-
  - अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री:
  - मोटरवाहनों की खरीद और बिक्री,
  - 50,000 रुपए से अधिक के भ्रोयरों का लेन-देन;
  - बैंक का नया खाता खोलना;
  - 50,000 रुपए से अधिक की सावधि जमाराशियां,

- टेलीफोन कनेक्शन के आवंटन के लिए आवेदन;
- 'होटलों को 25,000 रुपए से अधिक का भुगतान।

कम्प्यूटरीकरण के बढ़ते हुए प्रयोग से इस आंकड़े का उपयोग कर आधार बढ़ाने और राजस्व हानि रोकने के लिए पूरी तरह किया जाएगा।

- 94. हमें यह मानना चाहिए कि जटिल प्रक्रियाओं के साथ साथ आयकर संबंधी हमारे प्रपन्नों को भरने की बोझिल प्रकृति किसी भी ईमानदार व्यक्ति के लिए निर्धारिती बनने में गंभीर बाधा है। अतः मैं पहली बार साधारण एक पृष्ठ वाले कर दाता अनुकूल विवरणीपत्र, जिसे इसके बाद "सरल" कहा जाएगा, शुरु करने का प्रस्ताव करता हूं, जो सभी गैर-कंपनी करदाताओं पर लागू होगा। "सरल" को किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा कर सलाहकार की सहायता के बिना सरलतापूर्वक भरा जा सकेगा। मैं आशा करता हूं कि "सरल" स्वैच्छिक अनुपालन और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से काफी लोकप्रिय हो जाएगा। मैं महत्वूण शहरों के लिए मोबाइल बैन की सहायता से इसे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखता हूं, इस व्यापक रूप से स्थल पर ही सरलतापूर्वक बाटा और एकत्र किया जा सकता है। यह हमारे प्रयासों को और व्यापक बनाने में सहयोग प्रदान करने के अतिरिक्त संभावित कर-निर्धारितियों के दिमाग में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक असर भी पैदा करेगा।
- 95. मुकदमेबाजी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए अभिशाप रही है। राजस्व विभाग की काफी शक्ति लंबी अविध से विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में लिबित पड़े मुकदमों में नष्ट हो रही है। ऐसे विवादों में काफी राजस्व भी फंस जाता है। इस प्रणाली की रुकावटों को समाप्त करने से ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार काफी पहले ही अपना उचित बकाया वसूल कर सकेगी और प्रशासनिक उपायों के साथ प्रणाली को उपयोग कर्ताओं के अधिक अनुकूल भी बनाया जा सकेगा। अतएव में, "समाधान" नामक एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। यह स्कीम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लागू होगी और वर्तमान दरों पर प्रत्यक्ष कर के बकाया भुगतान पर ब्याज तथा जुर्माने की माफी तथा मुकदमा चलाने से मुक्ति प्रदान करेगी। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, जहां हाल के वर्षों में दरों का समायोजन बहुत अधिक रहा है, ब्याज और जुर्माने की माफी और मुकदमा चलाने की मुक्ति सहित शुल्क की 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
- 96. मुकदमेबाजी को सीमित करने और उसका निपटारा करने के लिए कानूनी उपायों का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। इनमें अपीलीय आयुक्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए फीस की सीमा बढ़ाना, उपायुक्त (अपील) के स्तर को समाप्त करना, विलम्ब कम करने के लिए उच्च न्यायालयों में सीधे अपील करने का प्रावधान और निवासी करदाताओं की अधिसूचित श्रेणियों के लिए अग्रिम निर्णय देने हेतु प्राधिकार की सीमा का विस्तार करना भी शामिल है।

- 97. संतुलित दरें और बड़ी रियायतें साथ-साथ नहीं चलतीं। अतएव मैंने आयकर अधिनियम के अधीन विभिन्न रियायतों और छूटों की समीक्षा की है। मैंने पाया कि उनमें से कई अब आवश्यक नहीं है और उनमें से कुछ का कर अपवंचन के लिए भी प्रयोग हो रहा है। अतएव, मैं इनमें से कई उपबंधों को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें भारतीय निर्यात-आयात बैंक को छूट और भारत में नियोजित विदेशियों की कतिपय परिलब्धियों के संबंध में छूट शामिल है। शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों के संबंध में पूर्ण छूट, जिसका गलत उपयोग हो रहा है, को वापस लेने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे संस्थान एक अनुशासन के अधीन आने के लिए बाध्य होंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों क्षेत्रों में वास्तविक रूप से सामाजिक हित के लिए कार्यरत संस्थान वर्तमान लाभों से विचित नहीं रहें, सुरक्षात्मक उपाय भी प्रदान किये जा रहे हैं।
- 98. मैं कतिपय खामियों को दूर करने का भी प्रस्ताव करता हूं। जीवन बीमा कारोबार से भिन्न बीमा कारोबार के लाभ की गणना करने से संबंधित आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 (क) को राजस्व की हानि रोकने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार, इस अधिनियम की धारा 10 (23छ) को रियायत के दुरूपयोग के बिना आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का उद्देश्य पूरा करने के लिए दुबारा तैयार किया जा रहा है। मौजूदा उपबंधों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य प्रणाली नहीं है कि किसी आधारभूत संरचना उद्यम द्वारा जुटाई गई कर-मुक्त निधियों का प्रयोग वास्तविक रूप से आधारभूत संरचना विकास के लिए किया जा रहा है न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। मैं ऐसी कार्य प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 99. उपहार-कर भारत में वर्ष 1958 से लगाया जाता रहा है। इस कर सें राजस्व प्राप्ति बहुत कम रही है। पिछले वर्ष हमने मात्र 9 करोड़ रुपए एकत्र किए। उपहार-कर अधिनियम भी कर अपर्वचन रोकने के एक साधन के रूप में सफल नहीं रहा है। अतएव में, 30 सितम्बर, 1998 के बाद दिए गए उपहारों पर उपहार-कर लगाना समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही यह सुनिष्टिचत करने के लिए कि उपहार के कार्यतंत्र के माध्यम से आयकर राजस्व की हानि नहीं हो, में प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाले उपहारों पर आयकर-अधिनियम के अधीन ही कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त होने वाले अनिवासी भारतीयों सहित अनिवासियों से उपहारों पर मौजूदा छुट जारी रहेगी।
- 100. मैंने पहले ही कहा है कि आवास व्यवस्था ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमें अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतएव, मैं आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें निम्नलिखित शामिल है:
  - अनुमोदित आवास परियोजनाओं के लिए कर अवकाश-प्रथम पांच वर्षों के लिए लाभों से 100 प्रतिशत कटौती और परवर्ती पांच वर्षों के लिए 30 प्रतिशत कटौती।

- आवास संपत्ति से आय के एवज में विधित कटौतियां- मरम्मतों तथा संग्रहण प्रभारों के लिए कटौती 1/5 वें हिस्से से बढ़ाकर एक चौथाई करना और स्वयं कब्जा की गई संपत्ति के मामले में उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के लिए कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करना।
- आवासीय संपत्ति से हुई हानियों को भावी आय में उसी शीर्ष के अधीन
   8 वर्ष तक आगे लाने की अनुमति दी जाएगी।
- विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त आवास परियोजनाओं में सलग्न कंपनियों
   के लिये होने वाले लाभों के 50 प्रतिशत के बराबर कटौती।
- अदा किए जा रहे किराए के लिए कटौती के संबंध में धारा 80 छछ को पुनः लागू किया जा रहा है।
- धन-कर अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक परिसरों जैसी कतिपय निर्दिष्ट संपत्तियों को छूट।
- 101. सामाजिक क्षेत्रक के अन्य क्षेत्रों, जिसके लिए नए कर प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है अथवा मौजूदा प्रोत्साहनों को बढ़ाया जा रहा है, में रोजगार सृजन, पर्यावरण का सुधार, महिलाओं का उत्थान, सड़क सुरक्षा, सहकारी समितियां और अपेगों को चिकित्सा व्यय देना शामिल है।
- 102. मैं कंपनियों को उन्हें अतिरिक्त कार्यबल नियोजित करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई कटौती का प्रस्ताव करता हूं। नये कामगारों को अदा किए गये अतिरिक्त वेतनों के 30 प्रतिशत के बराबर राशि को कतिपय शतों के अधीन, लाभों पर कटौती के रूप में मानने की अनुमति दी जाएगी।
- 103. पर्यावरण के सुधार के लिए, मैं जैव अपिशष्ट उत्पाद संग्रहण और प्रसंस्करण में लगे उपक्रमों को 100 प्रतिशत कटौती, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी, की अनुमित देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं जीवाणु से उत्पन्न उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को आय-कर अधिनियम की धारा 35 कग के तहत 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। इस प्रयोजन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन अधिसूचित किये जाएंगे। इसी तरह का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं और कारखानों अथवा परियोजना स्थलों पर नियोजित श्रमिकों के बच्चों के लिए शिश्चस्तवां और विद्यालयों की स्थापना करने और उन्हें चलाने सम्बन्धी गतिविधियों को देने का भी प्रस्ताव है। मैं सड़क सुरक्षा और यातायात के सम्बन्ध में जागरूकता को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने वाली गतिविधियों को धारा 35 कग के अधीन 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र बनाने हेतु नियमों में इसी प्रकार के संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं।
- 104. देश में खेल-कूद को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। मैं राष्ट्रीय क्रीड़ा निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और यह भी प्रस्ताव करता हूं कि निधि में दिए गए दानों पर 100 प्रतिशत कटौती की सुविधा दी जाएगी।

- 105. मैं किसी औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य या जिले में स्थित औद्योगिक उपक्रमों को प्रदत्त करावकाण को वर्ष 2000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं करावकाण में इसी प्रकार का विस्तार विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष 2003 तक और 1 अक्तूबर 1998 के वाद स्थापित नई शोधशालाओं के लिए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं अन्तर्देशीय जलमार्गों और अन्तर्देशीय पत्तनों को भी आधारभूत संरचना के दर्जे में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 106. मैं इसके अतिरिक्त रेडियो पेजिंग सेवाओं और दूरसंचार के लिए उपग्रह स्वामियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए करावकाण लाभों का प्रस्ताव करता हूं।
- 107. मैं व्यापार और उद्योग जगत की मांगों के प्रत्युत्तर में भी कई उपायों का प्रस्ताव करता हूं। आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप ऐसे पुनर्संगठन की आवश्यकता को देखते हुए व्यापार पुनर्संगठनों की कित्तपय श्रेणियों को किसी अतिरिक्त कर देयता अथवा कर लाभों की हानि से मुक्त करने का प्रस्ताव है। विनिर्दिष्ट पुनर्संगठनों के मामले मे कोई पूंजीगत अभिलाभ प्रभार्य नहीं होगा और क्षतियों को आगे ले जाने और अनामेलित मूल्यहास का लाभ दिया जाएगा। अमूर्त परिसम्पत्तियों को 25 प्रतिशत की दर पर मूल्यहास की अनुमित देने का प्रस्ताव है। आरम्भिक खर्चों के लिए परिशोधन के उपबन्धों को भी उदार बनाए जाने का प्रस्ताव है। परिशोधन की अविध 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है और इसके परिणामस्वरूप कटौती की दर दुगृनी की जाएगी। स्टॉक उधारी को पूंजीगत अभिलाभों से छूट देने का प्रस्ताव है।
- 108. वसूले गए अधिक कर की वापसी में विलम्ब नाइंसाफी के समान है। यह विशेषरूप से छोटे करदाताओं के निरन्तर उत्पीड़न का एक कारण है। मैं आयकर अधिनियम की धारा 192 में एक संशोधन कर इस कठिनाई का निवारण करना चाहता हूं जिससे वेतन आय में भवन सम्पत्ति से हानि का स्रोत पर ही समायोजन हो सकेगा, मुझे विश्वास है कि इससे बड़ी संख्या में वापसी के दावों में कमी आएगी।
- 109. कर दाताओं की मांगों के प्रत्युत्तर में, मैं और उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं। आय कर अधिनियम की धारा 44 कक के अधीन विद्यमान उपबन्धों के अधीन व्यापार अथवा व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, यदि व्यापार से उसकी आय 40,000 रुपए से अधिक है अथवा उसका कुल कारोबार 5 लाख रूपए से अधिक है, लेखा बहियां रखना अपेक्षित है। लेखाकारों को नियुक्त करने की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए मैं इन सीमाओं को बढ़ाकर क्रमणः 1,20,000 रुपए और 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आगे यह प्रस्ताव करता हूं कि धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर कटौती अथवा वसूली के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अथवा धारा 197 क के अधीन घोषणाओं की प्रतियां देने में विफलता के लिए 100 रुपए प्रतिदिन की न्यूनतम दर पर लगाया जाने वाला दण्ड, कटौतीयोग्य अथवा वसूलीयोग्य कर की राणि से अधिक नहीं होगा। इस समय लगाए जाने वाले दण्ड की मात्रा पर ऐसी कोई सीमा नहीं है जो, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए दिक्कते पैदा करती हैं।

- 110. फिल्म उद्योग की कतिपय मांगों की तरफ भी मेरा ध्यान गया है और मैं उन्हें राहत देने का प्रस्ताव करता है। विद्यमान नियमों के अधीन, यदि कोई फिल्म वाणिज्यिक आधार पर पूर्व वर्ष की समाप्ति से कम से कम 180 दिन पूर्व रिलीज की जाती है तो फिल्म निर्माण या फिल्म के वितरण अधिकारों के अधिग्रहण पर आई लागत पर रिलीज किए जाने वाले वर्ष में ही पूर्ण परिशोधन की अनुमति दी जाती है. जबिक यदि फिल्म बाद में रिलीज की जाती है तो उस वर्ष में पूर्ण परिशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आजकल फिल्म निर्माता और वितरक वीडियो-घोरों और केबिल टेलीविजन के खतर से बचने के लिए एक साथ बड़ी संख्या में प्रिंट जारी करते हैं जिसके परिणामस्वरूप फिल्मों के इस्तेमान की कालावधि कम होने लगी है। मैं 180 दिनों की उपर्युक्त अवधि को घटाकर 90 दिन करने का प्रस्ताव करता है। इससे फिल्म उद्योग फिल्म निर्माण और वितरण की लागत की शीघ्रतापूर्वक पूर्ति कर सकेगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हं कि ऐसे फिल्म निर्माताओं को जिन्हें किसी वित्तीय वर्ष में 5000 से अधिक की सभी अदायगियों के सम्बन्ध में आयकर विभाग की सूचना देना अपेक्षित है, अब केवल 25,000 रुपए से अधिक की अदायगियों के सम्बन्ध में ऐसा करना होगा। मुझे आशा है कि इन उपायों से फिल्म उद्योग को वेहतर और स्वस्थ फिल्मों के निर्माण की प्रेरणा मिलेगी।
- 111. हाल ही में धन ऐंठने के रूप में किये गये भुगतानों के लिए कटौती के बारे में एक विवाद उत्पन्न हुआ है। इस विवाद को प्रान्त करने के लिए में आय-कर अधिनियम 1961 के अधिनियमन के समय से भूतलक्षी प्रभाव से स्पष्ट रूप से यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं कि धन ऐंठने के रूप में अदा की गई कोई भी धनराशि व्यापार खर्च के रूप में कटौती की अईता प्राप्त नहीं करेगी। यौक्तिकीकरण के और उपायों के रूप में में माल सूचियों और पूंजी परिसम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण के बलाक निर्धारण प्रक्रिया और आशोधित मूल्य योजित कर (मॉडवेट) ऋण के निरूपण के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
- 112. व्यय कर लगाने के प्रयोजनार्थ होटलों में कमरे के किराए की सीमा 1200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव है।
- 113. समूचे विश्व के करदाताओं में सरकार को उनकी वैध देयताओं का भुगतान करने में गर्व का एहसास होता है और समाज उनके द्वारा राज्य को उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के इस महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। खेद है कि इस देश में ईमानदार करदाता द्वारा गर्व की अनुभूति और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सामाजिक मान्यता की संस्कृति अभी विकसित नहीं हुई है। हमें इस मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। इस प्रयोजन के लिए में राष्ट्रीय उद्देश्य से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए समाज की मान्यता प्रदर्शित करने हेतु "सम्मान" नामक एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। करदाताओं और स्थाई खाता संख्या धारकों को प्रदत्त सुविधाओं और मान्यताओं के ब्यौर अलग से घोषित किए जाएंगे।
- 114. मुझे आशा है कि सरल, सम्मान और समाधान के साथ-साथ उपर्युक्त उपाय करदाता अनुपालन को बढ़ाने के हमारे प्रयासों को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

लेकिन जहां एक ओर हम वह सब कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर मैं भारत के लोगों का आहवान करता हूं कि वे देश के प्रति अपने देशभक्ति पूर्ण दायित्व का निर्वाह करें और ईमानदारी से अपने करों की अदायगी करें।

- 115. इससे पूर्व कि मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर बढ़ं, मैं यह कहना चाहूगा कि करदाताओं के सभी तबकों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए थे और मैंने सावधानीपूर्वक उनकी जांच करवाई है। इन सभी पत्रों की अलग-अलग पावती भेजना व्यावहारिक नहीं है। मैं अब सामूहिक रूप से ऐसा कर रहा हूं और करदाताओं के प्रति उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए अत्यन्त आभारी हूं।
- 116. माननीय सदस्य बजट दस्तावेजों से यह देखेंगे कि प्रत्यक्ष करों से राजस्व उगाही के रूप में अनुमानित आंकड़े 48,855 करोड़ रुपए हैं जो अन्तरिम बजट में दिए गए आंकड़े से अधिक हैं। यह सदन के समक्ष रखी गई राहतों और रियायतों के कितपय प्रस्तावों से उत्पन्न होने वाले, यांत्रिक आधार पर परिकलित, 950 करोड़ रुपए की राजस्व हानि को हिसाब में लेने के बाद है। हम बकाया राशियों की वसूली में सुधार लाकर, कर आधार को व्यापक बनाने के प्रयासों में निरन्तरता लाकर, बजट प्रस्तावों में प्रतिबिम्बित कठोर प्रवर्तन और निवारक उपायों के जिए इस क्षित की पूर्ति करने और बजट में अनुमानित राशि की वसूली का इरादा रखते हैं।
- 117. अध्यक्ष महोदय, हमारा मध्यावधिक उद्देश्य कर एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाना है। जहां तक सीमाशुल्कों का संबंध है, इनकी पुनर्सरचना की प्रक्रिया से टैरिफ में उत्तरोत्तर कटौती हुई है जिससे अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य स्तरों के अनुरूप इन्हें लाया जा सके और कर दरों को व्यापक बनाया जा सके। इन उपायों से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पद्धात्मकता में वृद्धि हुई है।
- 118. उत्पाद शुल्क के मामले में, कुछ वर्ष पहले तक इस क्षेत्र में अनेक दरें विद्यमान थीं और यह अनेक तदर्थ छूटों से बाधित था। इसके परिणामस्वरूप कर संरचना सुस्पष्ट नहीं थी। करों को अत्यधिक रूप से युक्तिसंगत बनाकर इस प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाना वर्तमान प्रस्तावों का उद्देश्य है। इस प्रक्रिया का अन्तिम उद्देश्य केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वेट) की दिशा की ओर कदम बढ़ाना है जिसे इसके बाद सामान्य मूल्यवर्धित कर प्रणाली में आमेलित किया जा सकता है। हमारा इरादा इस व्यापक दिशा की ओर बढ़ने का है।
- 119. घरेलू उद्योग ने सीमा शुल्कों की पुनर्सरचना के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है और प्रशंसनीय लोचशीलता प्रदर्शित की है। इन्हें विश्व प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मक कारगरता को सुधारने की भी आवश्यकता है। परन्तु उनकी कुछ न्यायोचित चिन्तायें भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस पृष्ठभूमि में इस संक्रमण के रुख का सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा ताकि किसी गम्भीर व्यवधान के बिना भारतीय उद्योग को व्यवस्थित रखने के लिए समायोजन प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके।

- 120. आयात शुल्कों की संरचना के बारे में मुझे उद्योग के एक बहुत बड़े वर्ग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने भी घरेलू उद्योग के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए मुझे लिखा है। अधिकांश मामलों में मांगे विविध एवं विषम हैं। इसके कारण स्पष्ट हैं। जहां आयातित कच्चे मालों और दूसरी सामग्रियों के उपयोगकर्ता अथवा तैयार आयातित मालों के उपभोक्ताओं को आयात शुल्कों में और आगे कटौती से लाभ मिलेगा, वहीं घरेलू उत्पादकों ने घरेलू उद्योगों के लिए तत्काल राहत हेतु युक्तिसंगत पैरवी की है।
- मैंने इन चिन्ताओं और प्रतिस्पर्द्धी दावों के बारे में काफी अधिक विचार किया है। मुझे इस स्पष्ट अक्षमता को मानना पड़ा है कि हमारे सामग्री कराधान का असर आयातित मालों की तुलना में स्वदेशी मालों पर पड़ता है। जहां स्वदेशी माल पर बिक्री कर और अन्य स्थानीय कर एवं भूल्क लगाए जाते हैं, वहीं आयात क्षेत्र अपनी प्रकृति के कारण इनसे बच जाता है। घरेलू उद्योग को इस समान स्तर पर लाने के जद्देश्य से मैं आयातों पर 8 प्रतिशत का एक अतिरिक्त गैर आशोधित मृल्य योजित कर भूल्क (नौन माडवेटेबल लेबी) लगाने का प्रस्ताव करता हूं जो लगभग घरेलू उत्पादकों पर स्थानीय करों के बोझ के बराबर है। इस भूल्क को एक संरक्षणात्मक उपाय के रूप में नहीं बल्कि एक समान स्तर पर लाने की न्यायसंगत मांग के रूप में देखा जाना चाहिए। यह नया भूल्क एक विशेष टैरिफ संरचना के अन्तर्गत कच्चे तेल. अखबारी कागज, पूजीगत माल क्षेत्रक या बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादशुल्कों के अधीन आने वाले माल और यात्रियों या दूसरी नामित एजेंसियों द्वारा आयातित सोने और चोदी और सीमा शुल्क से मुक्त जीवन रक्षक औषधियों पर लागू नहीं होगा। यह शुल्क ऐसे माल पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें सीमाशूल्क के प्राथमिक अथवा अतिरिक्त शुल्क दोनों से इस समय छूट मिली हुई है। इसी तरह परवर्ती व्यापार के लिए आयातित मालों को भी इसकी परिसीमा से बाहर रखा गया है। चूकि वे पहली विक्री के समय बिक्री कर का बोझ वहन करते हैं अतः नया शुल्क निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत आयातित निविष्टियों पर भी लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी छूट के लिए पात्र हो सकते हैं। इनकी जांच की जाएगी और अगर उपयुक्त समझा गया तो इसे अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- 122. गत कुछ वर्षों में आयात शुल्कों में धीर-धीर कटौती करने से कुछ विकृतियां और विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। मेरे प्रस्ताव शुल्क संरचना में एकदम कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना जहां तक सम्भव हो, उन्हें सुधारने के लिए हैं।
- 123. इस्पात उद्योग ने विगत में सीमाशुल्क में की गयी क्रमिक कटौती को सहन करने में पर्याप्त क्षमता दिखायी है। परन्तु पिछले वर्ष इस्पात उद्योग ने कोई सराहनीय प्रगति नहीं दिखाई है। मैं लोहे और इस्पात की कोल्ड राल कायल्स पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं स्टैनलैस स्टील मैल्टिंग स्क्रैप पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और ताप सह्य मृदिका सामान पर 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास

है कि आयातों पर मेरे द्वारा प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त शुल्क को लगाने के साथ-साथ इन परिवर्तनों से सामान्यतः इस्पात उद्योग को पर्याप्त राहत मिलेगी।

- 124 पिटवा तांबे पर भुल्क 30 प्रतिभत से बढ़ाकर 35 प्रतिभत किया जा रहा है।
- 125. लौह और अलौह धातुओं पर लागू शुल्क संरचना में किसी परिवर्तन का मेरा विचार नहीं है।
- 126. वस्त्र उद्योग में डीएमटी, पीटीए, एमईजी जैसे मध्यवर्ती माल पर 25 प्रतिशत गीमाशुल्क लगाया जाता है। परन्तु 'केप्रोलक्टम' जो नाइलोन धागा तैयार करने के लिए कच्चा माल है, पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है। मैं केप्रोलेक्टम पर भी शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत कर रहा हूं ताकि वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित सभी बड़े मध्यवर्ती माल पर शुल्क की यही दर लगायी जा सके। 'पैराक्सिलीन' जो सिथेटिक रेशा और धागा तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री है, पर आयात शुल्क 15 प्रतिशतं से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा रहा है।
- 127. वस्त्र उद्योग का विकेन्द्रीयकृत क्षेत्रक, रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। इसकी लागत कम करके इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मैं वस्त्र ग्रेड के अफ्रोधित ऊन पर सीमाणुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। अपिष्ठ उन और ऊन के 'गारनेटेड' स्टाक पर भी भुल्क इसी सीमा तक घटाया जा रहा है। मैं 'एसीटेट' और 'क्यूपरामोनियम फिलामेंट यानी पर भी भुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह 'विस्कोस फिलामेंट यानी और ऊन उद्योग के लिए आवश्यक मशीनरी को भी 10 प्रतिशत का रियायती भुल्क दिया जा रहा है।
- 128. मात्रा के संदर्भ में कागज और कागज बोर्ड के आयात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुधारने के लिए में कागज और कागज बोर्ड पर शुक्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है।
- 129. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार सूचना के अधिकार को महत्व देती है। इस अधिकार को और अधिक शक्ति देने की दृष्टि से में मानक अखबारी कागज पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। में काचित अखबारी कागज (ग्लेज्ड न्यूजप्रिट) पर शुल्क की यही दर लगाकर शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा, हमारा विचार अखवारी कागज को 8 प्रतिशत के सम्पूर्ण विशेष अतिरिक्त शुल्क की प्रयोज्यता से मुक्त रखने का भी है।
- 130. पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए प्रति वर्ग मीटर 51 ग्राम तक के वजन वाले हल्के लेपित कागज पर कुल 5 प्रतिशत तक शुल्क कम करने का भी मेरा प्रस्ताव है।
- 131. फोटोग्राफिक रसायनों पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। इसी तरह साइट्रिक एसिड पर शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है।

- 132. सिनेमा फिल्मों के बड़े रोल्स पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- 133. मोटर वाहनों के पुजों पर सामान्यतः 40 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाता है। परन्तु मोटर-गाड़ियों के लिए आई. सी. इंजनों (अन्तर्दह्न इंजनों) और उनके पुजों पर 20 प्रतिशत की कम दर पर शुल्क लगाया जाता है। मैं इन पर सीमाशुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 134. मैं औद्योगिक हीरों पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे हीरा तराशी औजार उद्योग को मदद मिलेगी।
- 135. शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाए जाने के उपाय के रूए में रेयन ग्रेड के काष्ठ लुग्दी पर मैं शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करतः हूं।
- 136. थैलेसेमिया (रक्त विषाक्तता) जीवन के लिए एक घातक रक्त जिनत बीमारी है। 'माल्टोल' जो इस बीमारी के उपचार के लिए औषधि तैयार करने में प्रयुक्त एक पदार्थ है, में छूट देने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। में 'माल्टोल' को सीमाशुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। 'हाई ड्राक्सी इथाइल स्टार्च' और 'डेक्सट्रान' का उपयोग कृत्रिम प्लाज्मा तैयार करने में किया जाता है जो आयात शुल्क से मुक्त है। में 'हाई ड्राक्सी इथाइल स्टार्च' और 'डेक्सट्रान' पर शुल्क घटाकर 30 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करके कृत्रिम प्लाज्मा पर शुल्क का भार कम करने का प्रस्ताव करता हूं। में 'एइस' के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 'लाम्विडिन' को सीमाशुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं। '
- 137. चमड़ा उद्योग का हमारे निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए में चमड़ा उद्योगे के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर शुक्क 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह दर चमड़ा काटने वाली मशीनरी पर भी लागू होगी। मैं काठी के ढांचे (सैंडल ट्री) पर भी शुक्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 138. महोदय, इस सदन को जात है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी करार में शामिल हुआ है। हम सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह इसलिए नहीं है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी करार से बंधे हुए हैं बल्कि हम इस बात से आश्वस्त हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार और सूचना का अधिक स्वतंत्र आदान-प्रदान मानव कल्याण एवं उसकी सफलता की एक कुजी है। में 'फ्लापी डिस्क ड्राइक्स, हार्ड डिस्क ड्राइक्स' और 'सीडी-रोम ड्राइक्स' पर शुल्क कुल 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रति अदद एक हजार से अधिक मूल्य के 'आई सी' पर भी शुल्क कम करके 5 प्रतिशत किया जा रहा है। में कम्प्यूटर पुर्जी पर, 'पीपीसीबी' को छोड़कर शुल्क कुल 15 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। 'पीपीसीबी' पर शुल्क कुल 25 प्रतिशत से घटाकर

22 प्रतिशत किया जा रहा हैं। मैं कम्प्यूटर के रंगीन मानीटरों के लिए कथोड़ किरण ट्यूबों पर शुल्क कुल 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और रंगीन मानीटरों के विक्षेपक पुर्जों पर कुल 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है। मेरे प्रस्तावों में दूर संचार साफ्टवेयर पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना भी शामिल है। ऐसे साफ्टवेयर पर इससे आगे कोई अतिरिक्त सीमाशुल्क नहीं लगाया जाएगा।

- ं 139. देशी दूरसंवार उपस्कर क्षेत्रक को प्रोत्साहन देने के लिए मैं ऐसे उपस्कर के पुर्जी पर भुत्क घटाकर 20 प्रतिभात करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 140 पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के लपाय के रूप में, चिरी हुई लकड़ी और कुछ अन्य किस्मों की लकड़ी पर में आयातशुरू 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। में जैवकीटनाशकों जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर शुरू 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गैंने 'मेण्बेन इलेक्ट्रोलाइजर्स' और इसके पुर्जों पर शुरू 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
- 141. ऊर्जा बचाने वाले धातु 'स्थोड्मीन' पर शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया ज़ा रहा है। 'सिलिकान' जिसका उपयोग सौर ऊर्जा प्रयोगों में व्यापक रूप से किया जाता है, मैं विद्यमान 10 प्रतिशत शुल्क का आधा करने का प्रस्ताव करता है।

मैं निम्नलिखित पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूं:

- मोलर सैल और माइयूल्स पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
- \* बटन सैल पर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत
- 'वाच मूबमेंट' पर 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
- \* डीसी माइक्रो मोटर्स पर 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
- 'सीडी मैंकेनिज्म' पर 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत।
- 142. अध्यक्ष महोदय, अच्छी सड़कें सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आवश्यकताएं हैं। मुझे विश्वास है कि हममें से जो निजी वाहनों की सुविधा रखते हैं, वह देश में अच्छी सड़कों के तीव्र विकास में योगदान कर सकते हैं। मैं पैट्रोल पर तत्काल प्रभाव से प्रति लीटर एक रुपए की दर से अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे एक वर्ष में 790 करोड़ रुपए की धनराणि प्राप्त होने की आणा है जिसका उपयोग सड़कों के विकास के लिए किया जाएगा और यह सम्पूर्ण धनराणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संचित निधि को बढ़ाने के लिए दी जाएगी। मैं राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए उपस्करों के आयात को इस समय उपलब्ध रियायतें दूसरी सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

- 143. स्वर्ण के आयातकर्ता राष्ट्रीय राजकीय में निश्चित रूप से कुछ अधिक योगदान कर सकते हैं। मैं स्वर्ण पर आयात शुल्क प्रति 10 ग्राम 220 रुपए से बढ़ाकर 250 रु0 करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 144. इस समय साथ लाए जाने वाले सामान (वैगेज) पर शुल्क मुक्त छूट 6000 क0 है। अनेक देश इस प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, परन्तु हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते, अतः यात्रियों की निकासी में विलम्ब को कम करने के लिए वर्तमान सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। तीन दिन से अधिक समय तक रहने के बाद भारत वापस आने वाले यात्रियों के लिए मैं सामान की यह छूए 6000 कपए से बढ़ाकर 12,000 रु० करने का प्रस्ताव करना हूं। मैं तीन दिन से अधिक समय तक ठहरने के बाद विमान द्वारा नेपाल, भूटान, म्यामार या चीन से वापस आ रहे भारतीय निवासियों के लिए निःशुल्क छूट 3000 रु० करने का प्रस्ताव भी करता हूं।
  - 145. ऐसी अनेक मर्दे हैं जिन पर टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) की शार्तों के कारण सीमाशुल्क को थोड़ा कम करना आवश्यक है। मैं इसके विस्तृत ब्यौरों पर जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता।
  - 146. सरकार कर संहिता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है जो चरणबद्ध तरीके से पैट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली को समाप्त करने के अनुरूप है। वर्ष 2001 तक कच्चे तेल पर आयात शुल्क वर्तमान 27 प्रतिशत के स्तर से कम करके अधिकतम 5 प्रतिशत किया जाना है। 'फर्नेस आयल' 'एलएसएवएस' 'एचएसडी' मोटर स्प्रिट और 'एटीएफ' जैसे हितीयक उत्पादों पर भी आयात शुल्क घटाकर 10 से 15 प्रतिशत के स्तर तक लाया जाना है। इस प्रक्रिया में हम आयात शुल्क संरचना के उचित विभेदीकरण एवं मापन के द्वारा गौण उद्योग के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत का प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित करेंगे।
  - 147. मैंने नियंत्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली को हटाने से संबंधित निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। मैं कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क कुल 27 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में 965 करोड़ रुपए राजस्व हानि होने का अनुमान है। इस हानि को पूरा करने के लिए मैं मोटर स्प्रिट पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं समानान्तर विपणन के लिए आयातित मिट्टी तेल पर 2 प्रतिशत विशेष शुल्क सहित 32 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूं:
    - 148. अब में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर अपने प्रस्तावों का उल्लेख करता हूं।
  - 149. अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्रक के योगदान पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह रोजगार उत्पन्न करने का अति महत्वपूर्ण त्वरित माध्यम है और इस प्रकार यह हजारों परिवारों को सहायता प्रदान करता है। पूर्ववर्ती सरकारें लघु क्षेत्रक के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही हैं परन्तु मुझे सन्देह है कि उन्होंने उन्हें

प्रोत्साहित करने के लिए अधिक कार्य नहीं किया है जिससे उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो सके। अनेक वर्षों तक लघु क्षेत्रक को प्रदान किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन अपेक्षतया कम रहे हैं।

- 150. मैंने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं उत्पाद शुल्क प्रयोजन के लिए छूट सीमा 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं जो लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि है। 50 लाख रुपए से 100 लाख रुपए के बीच की स्वीकृतियों के लिए एक समान 5 प्रतिशत की सामान्य दर लगायी जाएगी, इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप एक वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी। हमारी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्रक को सुदृढ़ बनाने के लिए यह एक छोटी कीमत चुकानी होगी।
- 151. पिछले वर्षों में 'माडवेट क्रेडिट स्कीम' को काफी उदार बनाया गया है। परन्तु, प्राप्त किया गया माडवेट क्रेडिट हाल के वर्षों में अप्रत्याणित रूप से बड़ी तेजी से बढ़ा है जो दूरदराज के रेंजों में माडवेट योग्य बीजको की प्रति जाच के लिए व्यापक कम्प्यूटर नेटवर्क के अभाव में माडवेट क्रेडिट स्कीम के दुरूपयोग को प्रदर्णित करता है। जब तक ऐसा एक कम्प्यूटर नेटवर्क कार्य शुरू नहीं कर देता, में परिवर्तन के एक उपाय के रूप में उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों के मामले में भुगतान किए गए शुल्क के 5 प्रतिशत तक 'माडवेट क्रेडिट' की उपलब्धता को सीमित करने का प्रस्ताव करता है। परन्तु पूंजीगत माल के संबंध में 'माडवेट क्रेडिट' पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है।
- 152. उत्पाद शुल्क में दूसरे परिवर्तनों के बारे में मेरे प्रस्ताव, दर संरचना को युक्तिसंगण बनाने की समग्र आवश्यकता द्वारा मार्गनिर्देशित हैं तािक दरों की बहुलताओं को कम किया जा सके और यथामूल्य 18 प्रतिशत की औसत दर सुनिश्चित की जा सके। एक आदर्श कर संरचना वह होगी जहां औसत दर को छोड़कर छूट के योग्य मदों के लिए एक निम्न दर हो और छुट के अयोग्य माल के लिए एक उच्च दर हो। इससे दर में होने वाली घट-बढ़ और मध्यवर्ती दरों का दबाव कम होगा।
- 153. 'मैं औसत दर परिवर्तन की दिशा में पहले कदम के रूप में निम्नलिखित कुछ सामग्रियों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगान का प्रस्ताव करता हूं:
  - \* पैकेट बन्द चाय
  - ब्रांड युक्त मक्खन, पनीर और घी
  - \* हस्तचालित मशीन से भिन्न सिलाई मशीने
  - व्रांडयुक्त मसाले
  - फेक्ट्रियों में उत्पादित ब्रांडयुक्त खाद्य उत्पाद
  - ब्रांड नाम से बिकने वाले मांस और मछली उत्पाद
  - मक्खन सहित दूध पावडर जिसमें शिशुओं के लिए निर्मित दूध शामिल नहीं है।

- 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर
- \* चश्मे के शीशे और फ्रेम
- सरकवां कीलक (स्लाइड फास्नर्स)
- 154. मैं एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रूपए से अधिक की निकासी पर 5 प्रतिशत की एंक समान दर से प्लास्टिक की छूट वाली वस्तुओं पर भी उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं।
- 155. इसी तरह, मैं चिकित्सा यंत्रों और उपकरणों तथा प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों पर उत्पाद शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 156. अनेक सामग्रियों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इनमें से कुछ पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। अत. मैं इन वस्तुओं पर 13 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं।
- 157. इसके परिणामस्वरूप, माल्ट, कुछ प्रकार के डिब्बों, चिकित्सा फर्नीचर, धूप के चृश्मों और रिकार्ड न किए गए आडियो केसिटों पर आगे 13 प्रतिशत की दर से शुक्क लगाया जाएगा।
- 158. युक्तिकरण के उपाय के रूप में, मैं हथियार और गोलाबारूट पर शुल्क 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। परन्तु में सदन को 'आश्वासन देता हूं कि सैन्य सेवाओं के लिए हथियारों और गोला बारूदों के मामले में उत्पाद शुल्क की छूट जारी रहेगी।
- 159. में बहु-प्रयोगीय वाहनों पर शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत और ठोस अथवा कुशन टायर पर शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।
- 160. मैं संगसरमर की टाइल्स पर शुल्क प्रतिवर्ग मीटर 30 रुपए से बहाकर 40 रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हं।
- 161. मेरे प्रस्तावों में निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क में कटोती करना भी शामिल है:
  - मल जल शोधन संयंत्रों पर 13 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
  - 10 अश्व शक्ति तक के डीजल ईजनों पर 13 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
  - \* शल्य तथा चिकित्सा जांच दस्तानों पर 18 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
  - पोटेशियम आयोडेट पर 18 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
  - इलेक्ट्रोनिक केलकुलेटर पर 18 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत
  - पेजर पर 18 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत
  - सेलोफोन पर 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत
  - पीवीसी यौगिक पर 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत

- 162. मैं कृषि पर आधारित अपिषष्ट माल से बने काष्ठ रहित पार्टिकल बोर्ड और फाइबर बोर्ड पर 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की छूट का प्रस्ताव करता हूं। आगे से सीमेंट बाधित पार्टिकल बोर्ड, जूट पार्टिकल बोर्ड, चावल की भूसी से बने बोर्ड, ग्लास फाइबर युक्त जिप्सम बोर्ड, शीशल फाइबर बोर्ड और खोर्ड बोर्ड भी उत्पाद शुल्क से मुक्त रहेंगे। मैं 25 प्रतिशत से अधिक "फ्लाई एश" वाले ब्लॉक और ईटों, तैयार मिश्रित कंकरीट, जूट के कम्बलों, जूट नमदा को भी उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। अब 'पलटूडेड' जूट की वस्तुओं को भी उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।
- 163. मैं रिकार्ड किए गए आडिओ केसेटों को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं दूरदर्शन प्रसारण के लिए बने रिकार्ड किए गए वीडियो केसेटों को उत्पाद शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं। सभी साफ्टवेयर को शामिल करने के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर की छूट को अब व्यापक बनाया जाएगा।
- 164. घरेलू नाइलोन उद्योग कई कारणों से निष्क्रिय बना हुआ है। मैं नाइलोन फिलामेंट यार्न पर शुक्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्तव करता हूं।
- 165. करदाताओं द्वारा वित्त मंत्रियों की करों के बोस में वृद्धि करने की बाध्यकारी आदत के लिए प्रायः आलोखना की जाती है। तथापि, ऐसी शिकायत का औषित्य बाध्यकारी धूम्रपान करने वालों द्वारा नहीं किया जा सकता। मैं सिगरेटों पर विशिष्ट दरों के 6 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न मात्रा में उत्पादशुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता है।
- 166. मेरा धूम्रपान करने वालों के प्रति इस तरह कठोर व्यवहार करने का अभिप्राय नहीं है। तदनुसार में कुटीर उद्योग में विनिर्मित माचिसों पर उत्पादशुल्क प्रति सो डिबिया 0.50 से आधा घटाकर 0.25 रुपए तक करने का प्रस्ताव करता हूं। अन्य क्षेत्रकों द्वारा विनिर्मित माचिस के संबंध में भी अल्प कमी की जा रही है।
- 167. शुल्कों की उच्च दरों से अपवंचन और बचने की भावना उत्पन्न होती है।
  मैं अल्कोहल आधारित प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर
  50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इससे अनुपालन में
  सुधार होगा और राज्यों को और अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
- 168. कितपय उत्पादों के संबंध में पिछले वर्ष शुरू किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आधारित उत्पादशुल्क की प्रणाली का उद्योग द्वारा स्वागत किया गया है। यह स्कीम कराधान में सरलीकरण और निश्चितता की व्यवस्था करती है। मैं इस स्कीम को चाकलेट, माल्टयुक्त खाद्य निर्मितियों, काचित टाइल्स, रेजर ब्लेड, रेडियों सेट, घरेलू विद्युत उपकरणों और पान मसाला जैसी कुछ और वस्तुओं पर लागू करने का प्रस्ताय करता हूं।

169. पिछले बजट में कई सेवाओं को कर जाल में शामिल किया गया था। इनमें सड़क द्वारा माल की दुलाई पर प्रदान की गई सेवा शामिल हैं। सदन इस बात से अवगत है कि इसका व्यापक प्रतिरोध एवं विरोध हुआ था। इसके परिणामस्वरूप इस सेवा कर की अंततः वापस ले लिया गया था और ऐसा करना उचित ही था। इसलिए ही मैंने सड़क द्वारा माल की दुलाई पर सेवा कर समाप्त करने का निर्णय लिया है। मैंने बाह्य लान-पान प्रबंधकों और पंडाल के संविदाकारों द्वारा देय सेवा कर को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। तथापि, मैंने कुछ नई सेवाओं पर सेवा कर का प्रस्ताव किया है। ये निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई सेवाएं हैं:

- \* वास्तुकार
- आंतरिक सज्जाकार
- प्रबंध परामर्शदाता
- \* चार्टर्ड लेखाकार
- लागत लेखाकार
- \* कंपनी सिवव
- निजी सुरक्षा सेवाएं
- स्थावर संपदा एजेंट और स्थावर संपदा परामर्शदाता
- बाजार अनुसंधान एजेंसिया
- साख निर्धारण एजेंसियां
- हामीदारी एजेंसिया
- बड़े पशुओं के लिए यंत्रीकृत साधनों का प्रयोग कर रहे बूचड़खाने

हम इस बात की जीच करेंगे कि सेवा कर योग्य कितपय क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन में सुधार करने के लिए कैसे भुगतान का तरीके और माध्यम का और सरलीकरण किया जा सकता है। इन नए सेवा करों से पूरे वर्ष के लिए 220 करोड़ रुपए की आय होगी।

- 170. सीमाशुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों से एक वर्ष में 3,304 करोड़ रुपए का निवल अनुलाभ होना अनुमानित है। उत्पाद शुल्कों के मामले में, मेरे प्रस्तावों से 5,009 करोड़ रुपए का अनुलाभ होना अनुमानित है।
- 171. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमें अपने स्वैच्छिक अनुपालन का स्तर बढ़ाना चाहिए और हमारी कर संबंधी कार्यविधियां सरल, स्पष्ट और बाधारहित होनी चाहिए। हमारे कर कानूनों को अभी भी यह उद्देश्य प्राप्त करना है यद्यपि पहले काफी प्रयास किए जा चुके हैं।
- 172. हमारे कानून समय की आवश्यकता के अनुकूल नहीं है। यह अनिवार्य है कि उनका व्यापक आधार पर पुनर्निर्माण और उन्हें वास्तविक रूप से आधुनिक बनाने के लिए उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी है कि यह

एकं सरल कार्य नहीं है। परन्तु यह असंभव भी नहीं है। मैंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून को पुनः तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्णय लिया है। इस सदन के आगामी बजट सन्न में संसद के समक्ष नया उत्पाद-शुल्क कानून लाना मेरी सरकार का प्रयास होगा।

- 173. सरकार ने सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क से संबंधित विवादों की कतिपय श्रेणियों को निपटाने के लिए एक समझौता आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम का ब्यौरा वित्त विधेयक में निहित है। मैं विदेशी निवेशकों के लिए उनकी संभावित अप्रत्यक्ष कर देयता के लिए अग्रिम तौर पर आश्वस्त करने की आवश्यकता को देखते हुए उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क के लिए अग्रिम कर निर्णय के लिए एक प्राधिकरण गठित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इस आशय का एक विधेयक संसद में यथा-समय लाया जाएगा।
- 174. अध्यक्ष महोदय, अपने साहस, दृढ़निश्चय और दृढ़विश्वास से हमने पचास वर्ष पूर्व स्वयं को ब्रिटिश राज से मुक्त कराया था। इस वर्ष राष्ट्र गर्व के साथ स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है। तथापि, हमारा व्यापार और उद्योग जगत अभी भी एक अन्य राज, इसपेक्टर राज की जकड़न में बंधा हुआ है। हम जितनी जल्दी सम्भव हो सके, इसका खात्मा करने के लिए कृत संकल्प हैं। मेरा यह मानना है कि हमारा करदाताओं के प्रति यह दायित्व है कि हम उन्हें एक सक्षम, दक्ष, सुग्राही और सहानुभूतिपूर्ण कर प्रशासन प्रदान करें। वास्तव में ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
- 175. यह एक व्यापक धारणा है कि उत्पादशुल्क से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन से करदाताओं का उत्पीड़न होता है। हम गम्भीरतापूर्वक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए क्रमबद्ध परिवर्तन लाने के इच्छुक हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावित उपाय इस प्रकार हैं:-
  - अधिकारियों और करदाताओं के बीच सम्पर्क बिन्दुओं को न्यूनतम करना
  - \* ऐसे क्षेत्रों में कमी लाना जिनमें अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो
  - आयुक्त (अपील) और न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों को प्रतिष्ठा प्रदान करना
  - 'माडवेट' मामलों में द्वितीय अपील की प्रक्रिया को आसान बनाना
  - \* स्टाफ द्वारा कारखानों के दौरों को सीमित करना।
- 176. मैं इस तथ्य से विदित हूं कि सेवा कर से संबंधित प्रक्रियाओं और कानूनी दायित्वों के प्रति जबरदस्त असन्तोष है। मैंने कानून में कई अप्रीतिकर और सख्त उपबन्ध हटा दिये हैं। मेरा बहुत शीघ्र कई अनावश्यक और समस्याजनक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है।
  - 177. सीमाशुल्क के पक्ष में, मैंने 'फास्ट ट्रेक क्लीयरेंस सिस्टम' और आयात

निकासी में स्वयम् निर्धारण प्रणालियों के रूप में पहले ही की जा चुकी पहलों को सुदृढ़ करने का नर्णय लिया है। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों दोनों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाएगा ताकि करदाताओं और आयातकों तथा निर्यातकों से इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम रो सूचना प्राप्त की जा सके और इस प्रकार करदाताओं और विभाग के बीच सम्पर्क को कम किया जा सके।

- 178. मैं सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-बद्ध कार्रवाई की एक नई संस्कृति शुरू कर रहा हूं। नागरिकों के अधिकारों और सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण करने के लिए शीघ्र ही एक नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है।
- 179. सीमाशुल्क और उत्पादशुल्कों में उपर्युक्त परिवर्तनों को कार्यरूप देने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा-समय सदन के पटल पर रखी जाएंगी।
- 180. अन्त में मुझे अपने माननीय सहयोगी संचार मंत्री की तरफ से कुछ कहना है। डाक सेवा बड़े पैमाने पर रोजगार-परक है और वेतन और भत्ते डाक विभाग के प्रचालनात्मक खर्ची का एक मुख्य हिस्सा होते हैं। डाक सेवाओं के लिए शुल्क में संशोधन अपरिहार्य हो चुका है। तथापि, आम आदमी और लोकतन्त्र में प्रिंटमीडिया की भूमिका के हित में पोस्टकार्ड और पंजीकृत समाचारपत्रों के शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि, प्रतियोगिता पोस्टकार्ड की दर 2 रु० से बढ़ाकर 3 रु०, अन्तर्देशीय पत्र 1 रु० से बढ़ाकर 1.50 रु०, प्रत्येक 20 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पत्र की दर 2 रु० से बढ़ाकर 3 रु० और प्रत्येक 500 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पार्सली की दर 8 रु० से बढ़ाकर 10 रु० की जा रही है। कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं जिन्हें बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे। इन संशोधनों से एक पूरे वर्ष में लगभग 270 करोड़ रु० और 1998-99 में लगभग 180 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस मामूली वृद्धि से भी, जो डाक सेवाओं के विकास की निरन्तरता के लिए आवश्यक है, डाक सेवाओं की लागत केवल आंशिक रूप से ही पूरी हो सकेगी और लगभग 695 करोड़ रू० का डाक संबंधी घाटा पूरा नहीं हो पायेगा।
- 181. मेरे कर प्रस्तावीं और डाक शुल्क दरों में संशोधन के परिणामस्वरूप वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय घटकर 2,67,927 करोड़ रुपए हो जाएगा जबिक निवल राजस्व प्राप्तियां और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां बढ़कर 1,76,902 करोड़ रुपए हो जाएगी। राजस्व घाटा 48,068 करोड़ रुपए ओका गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 91,025 करोड़ रुपए ओका गया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत है। अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और विकास को प्रोत्साहित करने वाले व्यय की आवश्यकता को देखते हुए मेरा विश्वास है कि इस वर्ष इसमें अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है।

182. मेरा यह 'दृढ़ विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत विश्व-मंच पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा क्योंकि हम लोकतन्त्र और अमन-चैन के रास्ते पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं। मै आप सब का आह्वान करता हूं कि हमारे लोकतन्त्र को मजबूत करें, मैं आपका आह्वान करता हूं कि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के बेहतर भविष्य निर्माण में हमारे साथ कदम से कदम मिला कर चलें। यदि हम मेलजोल एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ें तो भविष्य निसन्देह हमारा है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में:

सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है; ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।

183. अध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं यह बजट इस महान सदन की प्रस्तुत करता हूं।

जे. एस. माथुर, अपर सचिव (बजट)

#### MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Economic Affairs) (Budget Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1998

No. F. 15(10)-B(D)/98.—The following is published for the general information:

Budget 1998-99
Speech of Shri Yashwant Sinha
Minister of Finance
Ist June, 1998
PART A

Sir,

I rise to present the budget for the year 1998-99.

#### Introduction

- 2. This is the first budget of the Government led by Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. It is a defining moment in history. It is an occasion fraught with expectation. I am very grateful to the Prime Minister for the confidence he has reposed in me and the guidance he has given me.
- 3. It has been just over ten weeks since this Government took office. But we know already that a new India is rising. And as May 11 was surely the first step, today is yet another. Certainly, a long journey lies ahead, but as history will prove, we have now begun to build a new India. This will be a strong and prosperous India a nation self-reliant, but not autarchic, rather a nation keen to deal with the world as an equal partner with other countries. As the saying goes, "only the strong can be free. And only the productive can be strong". This is the new India we propose to build.
- 4. The dimensions of the economic challenges that confront us today have come into sharper focus since the time I presented the interim budget before this House. While the people of India have reacted with pride over the events of May 11, some of our friends abroad have responded negatively. I am confident that these initial negative responses will be moderated as our position gets better understood, and will not have any significant impact

on our economic development. On our part, our policies have to be clearly directed and firm. As Gurudev Rabindranath Tagore said "You cannot cross the sea by standing and staring at the water". We intend to cross the sea and I seek the cooperation of this august House in this national endeavour in the weeks and months ahead.

5. In preparing this budget I have been guided by the famous talisman of Gandhiji. I have recalled to myself the face of the poorest and the weakest man I have seen and made sure that this budget is of use to him. This budget is rooted in Swadeshi which will be unfolded as we go along. But I shall hasten to add that Swadeshi does not mean isolation, Swadeshi means making India strong and self-reliant so that we can compete with the world and win. As our courageous Prime Minister has himself said:

लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रूकेगा।

Flag we hold shall never bow, Marching steps shall never halt.

#### **Current Economic Situation**

6. A few days ago the Economic Survey, 1997-98 was tabled in Parliament. It provides a comprehensive analysis of the economy's performance during 1997-98. In my interim budget speech I had already drawn attention to some disquieting trends: overall economic growth slowed to 5 per cent in 1997-98; agricultural growth was negative, with foodgrain production dropping to 194 million tonnes from 199 million tonnes in the previous year; growth of industrial production slackened to 4.2 per cent; export performance was weak for a second successive year, recording growth in dollar terms of less than 3 per cent; the fiscal deficit worsened to 6.1 per cent of GDP; the capital market remained in the doldrums and infrastructure bottlenecks continued to plague the economy. But I am not daunted by the situation. Only the weak are tamed by adversity, the strong rise above them.

# **Key Objectives**

- 7. Drawing on the National Agenda for Governance and policy statements of the Prime Minister, I believe the key objectives of this budget should be to:
  - \* Strengthen the foundations of the Indian economy to deal effectively with an inherently uncertain external environment.

- Reverse the decline in agriculture and strengthen the rural economy.
- Restore the momentum of industrial growth, especially of small scale enterprises, and revive the capital market.
- \* Accelerate the development of infrastructure.
- By these and other means, rapidly expand productive job opportunities.
- \* Give special impetus to social sector development.
- \* Calibrate the pace and character of integration with the world economy, while strengthening India's international economic position through revival of exports and reduced reliance on borrowed funds.
- \* Ensure macro-economic stability and control over inflation.
- \* Raise the rate of domestic savings to achieve higher national investment and thus lay the basis for faster medium-term growth. Supplement this effort through foreign investment.
- \* Free the productive energies of our people from unnecessary bureaucratic hurdles and undertake reforms to raise the productivity of our land, labour and capital.

## Agriculture and Rural Development

- 8. As I stand here and address this august House, my thoughts wander naturally to the remote villages of India and to millions of our toiling farmers. I have no doubt in my mind that the health and dynamism of the rural economy is central to India's economic and social development. I propose to do the following for agriculture and rural development:
  - \* Water is a critical input for agriculture. Yet, after all these years of development only 37 per cent of our cultivable area is under assured irrigation. The bulk of our poor people live in rainfed areas. We propose to accord top priority for development of rainfed areas on a watershed basis and thereby enhance agricultural productivity in a sustainable manner. Watershed Development Programmes, currently spread across several ministries and departments, will be unified and the plan allocation stepped up to Rs.677 crore from Rs.517 crore in RE 1997-98. Furthermore, there is an increase in the

provision for the Accelerated Irrigation Benefit Programme by 58 per cent over 1997-98.

- \* Next only to water is the question of rural credit and rural infrastructure. Under the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) managed by NABARD moneys are made available to the State Governments for rural infrastructure. During the past three years about Rs. 2.500 crore has been allocated to it annually. I am pleased to announce RIDF IV with an enhanced allocation of Rs.3,000 crore. I invite the States to come forward to utilise this important facility.
- \* I propose to augment NABARD's share capital by Rs.500 crore in the current year. Government will allocate Rs.100 crore from the budget and the RBI will contribute the balance of Rs.400 crore. This will enable NABARD to leverage additional resource from the market to meet the credit needs of agriculture.
- The problem of rural unemployment and underemployment is a massive one. This can only be solved through self-employment. There is no reason why every craftsman, artisan and weaver cannot become an entrepreneur and run his own little enterprise. A major bottleneck however has been lack of credit facilities Earlier NABARD had launched a limited scheme for promotion of Self Help Groups (SHG) as a channel for the flow of funds to the micro enterprises. I am asking NABARD to greatly extend the scope and coverage of the scheme so that 2 lakh Self Help Groups covering 40 lakh families can be assisted over the next five years through this scheme of micro credit. 10,000 Self Help Groups covering 2 lakh families will be assisted this year. The Reserve Bank of India is also advising commercial banks to design specific loan package to meet the needs of micro enterprises.
- \* I have asked the National Housing Bank to finance one lakh rural dwelling units under the Swarna Jayanti Housing Finance Scheme as against 50,000 units last year.
- I am making a provision of Rs.265 crore to carry forward the process of rehabilitation and recapitalisation of the Regional Rural Banks (RRBs). Sponsor banks are being given an enlarged role in providing management, operational and restructuring support to RRBs.

- \* Farmers often face chronic problems of overdue loans due to circumstances beyond their control. They are even committed to civil prison for this default. While the repayment culture must improve, this government is determined to create conditions so that no farmer goes to jail for a loan repayment default or is forced to commit suicide. The Reserve Bank will be issuing appropriate guidelines to the banks for hassle-free settlement of old cases of overdues. Banks will be encouraged to provide appropriate relief on accumulated interest in deserving cases. The new procedure should also help in reducing the outstanding volume of Non-Performing Assets (NPAs) of the banking sector.
- \* NABARD is being asked to formulate a model scheme for issue of Kisan Credit Cards to farmers on the basis of their holdings for uniform adoption by the banks so that the farmers may use them to readily purchase agricultural inputs such as seeds, fertilisers, pesticides etc. and draw cash for their production needs.
- 9. The ingenuity and enterprise of our farmers is today hamstrung by numerous Central and State laws and regulations relating to the production, marketing and movement of agricultural commodities. This is clearly unacceptable. My colleague, the Minister of State for Agriculture, will soon be bringing out, under the guidance of the Prime Minister, the Government's National Agricultural Policy paper which will address these constraints in a comprehensive manner. The Minister of Commerce is systematically reviewing existing controls on exports of all agricultural commodities except foodgrains. There is no reason why our farmers should not reap the benefits of access to wider global markets.
- 10. The system of agricultural cooperatives in our country is plagued by bureaucracy and political interference at many levels. As part of a concerted programme to revitalise the cooperative sector, government will shortly bring forward a model cooperative law to replace the Multi-State Cooperative Societies Act of 1984 and will encourage the States to make similar amendments in their own acts.
- 11. There has been a long standing demand from our farmers and the Ministry of Agriculture for the exclusion of farm implements and tools from the list of items reserved for manufacture by the SSI sector, so that farmers can benefit from a wider range of implements and tools at competitive prices and

with requisite after sales service. This proposal had also been recommended by the Advisory Committee of the Ministry of Industry. Government have decided to accept this recommendation.

- 12. India has made commendable progress in oilseeds production in recent years. In order to establish an efficient market environment and to reduce volatility in prices in this sector, the government is planning to introduce futures trading in edible oilseeds, their oils and their cakes.
- 13. The existing subsidy schemes for both urea and decontrolled phosphatic and potassic fertilisers are being continued. However, for achieving optimum crop response ratio to fertiliser use, the use of all the three nutrients, nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) should be balanced. This balance has been progressively distorted over time because of the low price of urea compared with decontrolled fertilisers. The NPK balance, which was 5.9:2.4:1 in 1991-92, had changed adversely to 10:2.9:1 by 1996-97. An increase in the price of urea would help restore this balance. The increase is also justified on the ground of rising costs, which have led to a more than 50 per cent increase in the subsidy on indigenously produced urea in two years between 1995-96 and RE 1997-98. It is, therefore, proposed to increase the selling price of urea by Re.1 per kilogram with immediate effect.
- 14. Government is committed to provide safe drinking water to all rural habitations in the next five years. To achieve this ambitious target, a multi pronged approach to rural water supply is being adopted:
  - \* The allocation for the Accelerated Rural Water Supply Programme is being enhanced from Rs.1,302 crore in RE 1997-98 to Rs.1,627 crore in this regular budget. This enhanced outlay will cover about one lakh habitations.
  - \* As mentioned earlier, we will give a special thrust to Watershed Development Programmes. This will also ensure better results for ground water availability and conservation.
  - \* States are being encouraged to institutionalise community-based rural water supply programmes, which secure active participation of beneficiaries to own, operate and maintain rural water supply facilities.

15. Over the years, programmes for alleviation of poverty and employment generation have proliferated. Each scheme is well intentioned but their multiplicity has led to needless duplication, high overhead costs, confusion at field levels and insufficient benefit to the people. It is proposed to unify the various programmes under two broad categories of Self Employment Schemes and Wage Employment Schemes. Funding and organisational patterns will be rationalised to achieve maximum beneficial impact of these programmes.

# Small Scale Industry

- 16. The SSI sector makes a valuable contribution of about 40 per cent to our total manufacturing sector production, 35 per cent to exports and employs over 160 lakh workers. Our commitment to the SSI sector is total. The commonest complaint of SSI entrepreneurs and associations are the insufficiency of timely credit and the harassment of the "Inspector Raj".
- 17. On the credit problems of the SSI sector, I propose the following initiatives:
  - At present, for SSI units having aggregate working capital requirements up to Rs.2 crore, the working capital limit is determined by the banks on the basis of a simple calculation of 20 per cent of their annual turnover. This facility is being doubled to Rs.4 crore. This will ease the flow of bank credit to SSI.
  - \* To moderate the cost of credit to SSI units, RBI will advise the banks to accord SSI units with a good track record, the benefit of lower spreads over the prime lending rate.
  - \* Enhanced powers would be delegated to bank managers of specialised SSI branches to ensure that most credit proposals are decided at the branch level.
  - \* At present, Small Industrial Development Bank of India (SIDBI) is a subsidiary of IDBI and IDBI is the major shareholder in State Finance Corporations (SFCs). To equip SIDBI to play its apex role in SSI credit provision more effectively, SIDBI will be delinked from IDBI and IDBI shareholding in SFCs will be transferred to SIDBI.
  - \* SSI units are often handicapped by delays in the settlement of their dues from larger companies. To tackle this problem, I am asking RBI to strengthen the existing mechanisms available to SSI for discounting of bills. RBI

will also modify its guidelines to commercial banks on credit appraisal to give greater weight to the amount of overdue outstandings that large units have in respect of SSI supplier. My colleague, the Minister of Industry is separately bringing amendments in the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industry Undertaking Act, 1993 to make the existing legislation more effective.

- 18. As for the pervasive problem of the "Inspector Raj", I shall be announcing far reaching changes in the administration of Central Excise which should help SSI units significantly. I urge all States to review their laws and regulations and make necessary changes to lighten the burden of the inspector raj problem of SSI units.
- 19. I shall also be announcing some tax concessions to the SSI sector later in my speech.

## Private Investment in Industry

- 20. The government accords high priority to boosting private investment, including foreign investment, in industry. We must minimise bureaucratic and procedural hurdles and create an investor friendly environment. Industrial licensing was abolished in most industrial sectors as part of the economic reforms. On reviewing the remaining handful of licensed sectors, the government have further decided to delicense coal and lignite and petroleum products.
- 21. Industrial deregulation would remain incomplete without reducing the burdens imposed by the "Inspector Raj". The majority of inspectors operate under State level statutes. Government have initiated a dialogue with the State Governments to explore the consolidation of regulatory legislation relating to industry and exchange of best practices across States in carrying out the necessary inspections in the least burdensome way. I will return to this subject when I present my excise proposals.
- 22. The Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has done a good job in promoting foreign investment and streamlining the procedures at the Central government level. Foreign investment flows have increased substantially and were estimated to be \$3.1 billion in 1997-98. About 60 per cent of investment approvals are in the energy and infrastructure sectors. It will be our objective to create conditions in which foreign investors will find India an attractive investment destination. We hope to double the inflow of

foreign direct investment within two years. Foreign investors are frequently inhibited by lack of familiarity with our systems and statutes and particular problems at the State level. To reduce such problems, we will implement a system whereby, an officer of the administrative Ministry would be designated as a monitoring officer to help processing and implementation of the project in conjunction with Central and State authorities for every foreign investment proposal exceeding Rs.100 crore. We are committed to creating a hassle-free procedure and I would like to assure all foreign investors that a decision on their investment proposals shall be taken within a period of 90 days. It will be the personal responsibility of the monitoring officer to ensure this.

## Housing

- 23. The National Agenda, identifies housing as a priority area. We will move purposefully to tackle the country's enormous housing shortage problem through partnership between government, housing finance institutions and the private sector.
  - \* 20 lakh additional dwelling units will be built this year with 13 lakhs in rural areas and 7 lakhs in urban areas.
  - \* The budget allocation for the Indira Awas Yojana Programme is being substantially enhanced to Rs. 1600 crore, from Rs. 1144 crore in RE 1997-98. The scope of this scheme is also being widened to include a loan-cumsubsidy programme.
  - \* The Urban Land Ceiling and Regulation Act will be repealed to free the supply of usable urban land for housing construction.
  - \* The capital base of the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) is being increased by Rs.110 crore from the budget so that it may leverage more funds for housing construction.
  - I also have some tax incentives for housing which I will outline later in my speech.

#### Infrastructure

. 24. The acuteness of our infrastructure problems is equalled only by our resolve to tackle them. One of the major planks of this budget is to provide strong stimulus to the infrastructure sector through larger public and private investment in these sectors. This will also help to boost industrial growth and overall economic activity.

- 25. The plan outlay for the key infrastructure sectors of Energy, Transport and Communications in the revised estimates for 1997-98 was Rs.45,252 crore. I am happy to announce that the outlay for these sectors for the current year will be Rs.61,146 crore. This is an increase of 35 per cent. I am hopeful that this steep increase in investments will trigger industrial activity and revive rapid economic growth.
- 26. Within a few weeks of taking office, the government passed an important ordinance for establishing Central and State Electricity Regulatory Commissions with the primary objective of rationalising electricity tariffs. This will go a long way towards enhancing investor confidence in the power sector and facilitate raising resources for higher public and private investment. We have also simplified the procedures for extending sovereign counter guarantees for a few "Fast Track" power projects which were held up for long. We now expect early financial closure of these projects. The total plan outlay for Ministry of Power is being increased to Rs.9,500 crore as against Rs.6,738 crore in RE 1997-98.
- 27. The outstanding dues from State Electricity Boards to major public sector undertakings such as NTPC and Coal India amount to about Rs.10,000 crore. These large outstanding dues are serious impediments to investment by these public sector undertakings. The government will evolve a guarantee scheme to cover such dues. On the strength of such guarantees, the PSUs concerned will be able to raise resources either by securitising these debts or directly entering the market for tapping resources. This would help these enterprises to raise resources to fund large projects in the power and coal sectors. The resulting investment will also boost industrial growth and investment through linkage effects.
- 28. We must build more roads and the quality of our roads must also improve. Our National Highways must be brought up to international standards. I am providing Rs.500 crore for the National Highways Authority of India to catalyse new road projects including four-laning of existing National Highways. I shall announce some more measures for this sector in Part B of my speech.
- 29. To enhance long-term finance for infrastructure investment in the private sector, the Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFC) was incorporated as—a non-government company in 1997. I am happy to inform the House that the IDFC has tied up its paid up equity capital of Rs.1,000

crore, including equity participation of Rs.400 crore by nine foreign investors and has now commenced operation. In order to put IDFC on par with other all India public Financial Institutions in the matter of fiscal incentives and fund raising benefits extended to these institutions, it is proposed to make necessary amendments to the Companies Act.

30. Provident funds are a potentially important source of funding for private sector infrastructure projects. The present pattern of investment prescribed for provident funds does not permit any investment in securities of private sector infrastructure projects. I propose to provide some flexibility in this regard by allowing upto 10% of the new accretion to provident funds to be invested in private sector securities which have an investment grade rating from at least two credit rating agencies. This is an enabling provision which will allow the Board of Trustees managing these funds to invest in these securities subject to their assessment of the risk-return prospects of each security.

#### Education

- 31. Education is the key vehicle for social transformation. Universalisation of elementary education and eradication of illiteracy are central elements of our social policy. Government also plans to implement the Consitutional provision for making primary education free and compulsory up to fifth standard and for girls up to the college level.
- 32. This budget provides for a nearly 50 per cent increase in the total budgetary allocation to Education, from Rs.4,716 crore in RE 1997-98 to Rs.7,047 crore in this budget. We are committed to raising the total resource allocation for Education to 6 per cent of GDP in a phased manner.
- 33. The allocations under the Kasturba Gandhi Shiksha Yojana and the Mahila Samiridhi Yojana will be integrated to support a unified Action Plan for accelerating female education.
- 34. Swami Vivekanand while exhorting the youth had said "A far greater work is the sacrifice of yourself for the benefit of your race, for the welfare of humanity." In order to harness the limitless energy of the youth, government will formulate a scheme for creation of a National Reconstruction Corps, which will mobilise youth for community-based nation building activities. The scheme will also promote self-employment of youth whereby the volunteers would simultaneously be given training in vocations and

entrepreneurship development for taking up self-employment vocations. An inter-Ministerial Committee is being set up to work out the details.

## Information Technology

- 35. The Prime Minister has underlined the crucial importance of Information Technology for India. It is the fastest growing sector of the Indian economy as indeed of the world economy. It has tremendous potential for the generation of employment, incomes and export earnings. It can also provide millions of skilled jobs for women. Our Information Technology specialists and software creators are second to none in the world.
- 36. The government have set itself a target of making India a Global Information Technology Power and one of the largest generators and exporters of software in the world within ten years. A National Information Technology Task Force, headed by the Deputy Chairman, Planning Commission has been set up, to formulate a National Informatics Policy which will help achieve our objectives.
- 37. Our software companies operate in a highly competitive global market and the skilled professionals working in these companies have attractive opportunities abroad. Our companies need flexible systems of incentives to retain their human resources. They have sought permission to offer stock option schemes to their Indian employees linked to ADR/GDR issues abroad, under which their employees will be eligible for ADR/GDR stock options. In recognition of the excellent work being done in this sector, and its very special circumstances, the government have decided to formulate a special scheme to allow such options for the software sector. The details of the scheme will be notified separately.
- 38. I also have some fiscal proposals to support rapid development of this crucial sector which I will present later in my speech.

## **Financial Sector**

39. A mature and well functioning financial system is essential for promoting savings, channelling investment into the most productive activities and ensuring an efficient payments mechanism. The East Asian financial crisis has highlighted the importance of prompt action to strengthen our financial system. The recently submitted Narasimham Committee Report has provided many recommendations which are being examined in

consultation with RBI. However, I am happy to announce that decisions have been taken on some important recommendations.

- \* The relatively high level of Non-Performing Assets (NPAs) in our public sector banks is a cause for concern. Net NPAs, averaging 9 per cent in 1996-97, must be brought down to below 5 per cent by the year 2000-2001. As one way of reducing NPAs, Debt Recovery Tribunals will be strengthened and more Tribunals will be set up to cover all States.
- \* A few banks have particularly high NPAs. These banks will be encouraged, on an experimental basis, to establish Asset Reconstruction Companies, which will takeover the NPAs of the bank at their realisable value and swap them with special bonds to be held by the bank. The Asset Reconstruction companies will concentrate on recovery of dues to realise the maximum value for the assets transferred to them.
- \* To strengthen the underlying health of our banks, RBI is raising the minimum required Capital Adequacy Ratio for banks from the present 8 per cent to 9 per cent by March 31, 2000 and to 10 per cent by as early as possible thereafter. RBI will also announce certain other enhancements of prudential norms in regard to asset classifications, income recognition, risk weights, etc.
- \* Our financial system today works under the burden of several archaic laws regarding transfers of and transactions in properties and financial instruments. An Expert Group is being set up to propose precise legal amendments in the key laws to make the provisions consistent with modern financial and banking practices.
- 40. Non-Bank Finance Companies (NBFCs) perform an important role in our financial sector. But regulation of this sector has to improve to protect unwary small investors. The Reserve Bank of India Act was amended last year with a view to laying down a framework for improved regulation of NBFCs. RBI has recently issued guidelines for registration as also for effective regulation of NBFCs. Our objective will be to develop a framework of prudential regulations and a supervisory system which will foster the development of a healthy financial system and also provide transparent disclosure norms leading to greater depositor awareness to enable the investors to take well informed investment decisions.

41. Along with reform of the banking sector, it is necessary to move forward with reforms in insurance which has hitherto been a public sector monopoly. In order to provide better insurance coverage to our citizens and also to augment the flow of long-term resources for financing infrastructure, I propose to open the insurance sector to competition from private Indian companies. The Insurance Regulatory Authority will also be converted into a statutory body. Necessary legislation will be introduced later in the year.

## FEMA and Money Laundering

- 42. The present Foreign Exchange Regulation Act, 1973 is outdated and is no longer in keeping with the needs of the economy and the changes that have taken place in foreign exchange markets and transactions. We have moved to full current account convertibility. It is no longer appropriate to deify foreign exchange as something special and maintain a burdensome and highly regulatory structure around this deity. Accordingly, government have decided to repeal FERA and replace it with a new Foreign Exchange Management Act (FEMA), which would be consistent with the needs of a modern economy. The new Bill will be introduced in this session of Parliament.
- 43. At the same time, I want to assure the House that the replacement of FERA by FEMA is in no way intended to give license for illegal transactions to drug peddlers, terrorists, arm smugglers and other perpetrators of heinous economic crimes. Indeed, to protect our society from the globally recognised and, growing problem of money laundering, I will also bring an anti Money Laundering Bill before the House simultaneously with FEMA.

#### Capital Market

- 44. I am proposing a number of measures to strengthen our capital markets:
  - The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has approved the introduction of trading in stock index futures as a way of providing greater opportunities for hedging and inducing more liquidity into the market. The government will bring forward the necessary amendment to the Securities Contracts (Regulation) Act to enable derivative instruments to be treated as securities.
  - Foreign institutional investor (FII) debt funds are today allowed to invest only in listed debt securities. I propose

to allow them to invest in unlisted domestic debt securities also; the risk of default would be borne by the FIIs.

- \* To encourage modernisation of broker services, a one time permission was given last year to stock brokers to corporatise their businesses without attracting capital gains tax. I propose to extend this exemption by one year.
- \* To encourage more primary public issues, I am proposing certain changes to expand the income tax deductibility of expenses incurred on public issues.
- \* After some of the turbulent events in the stock markets in recent years, a special effort must be made to restore the confidence of small investors. I am asking SEBI to devote special attention to strengthening the institutional arrangements for protecting small investors from defaults and financial failures of brokers and other market intermediaries.

#### Non-Resident Indians

- 45. Whenever I have travelled outside India, Non-Resident Indians (NRIs) have expressed a sincere desire to contribute meaningfully to the development of India. I believe NRIs constitute a huge, untapped potential for India's development. I propose the following steps to encourage NRIs to participate in the development of their country of origin:
  - At present NRIs are allowed to purchase shares in Indian companies in the secondary market subject to a limit of 1 per cent of the company's total equity for individual NRIs and NRI overseas corporate bodies, with a 5 per cent limit for aggregate NRI/OCB investments in the company. These limits were imposed many years ago when our capital market regulations were much weaker and there were no rules governing acquisition and takeovers. The situation has changed materially in both these respects. I, therefore, propose to raise the individual investment limit of 1 per cent for NRIs to 5 per cent and the aggregate limit for all NRI investments in a company from 5 per cent to 10 per cent.
  - \* NRIs have also complained to me that the procedures governing their participation in our share markets are extremely cumbersome and onerous. I am having these procedures thoroughly reviewed with a view to modifying them to facilitate investment by NRIs in our capital markets.

- \* The Unit Trust of India will launch a new India Millennium Scheme which will be open for subscription in dollars only by NRIs. The money collected under this scheme would be invested in shares of Indian companies with high potential for growth and in high quality Indian debt. The details of the scheme will be announced shortly.
- \* The State Bank of India is launching a new Resurgent India Bond denominated in foreign currencies for subscription by NRIs. This will enable NRIs to contribute to the flow of resources for our country's development, especially for building up infrastructure. The bond will be fully repatriable and the government will extend tax concessions similar to those currently available to NRI deposits to this new bond. The details of the scheme will be notified separately. I am confident that NRIs will welcome this initiative and will contribute liberally to these Bonds.
- 46. I have one more significant announcement to make for NRI's. Government have decided to draw up a scheme for issuance of a Persons of Indian Origin (PIO) Card for those living abroad and having foreign passports. The PIO Card, which would be extended to persons of Indian Origin settled in countries to be specified by government would besides introducing a visa-free regime, also confer some special economic, educational, financial and cultural benefits. The details are being worked out.

# **Decentralisation and Expenditure Restructuring**

- 47. Government have already appointed a Special Task Force on Devolution of Powers to States, under the Chairmanship of Shri Bhairon Singh Shekhawat, to examine and recommend measures for devolution of additional financial powers to the States and additional or alternative means by which States can raise more resources. The first report of the Task Force has been received. We are examining the recommendations in consultation with the RBI.
- 48. The distinction between plan and non-plan expenditures in our budgetary system has created several problems. It has led to an excessive focus on so called plan expenditures with a corresponding neglect of items such as maintenance which is classified as non-plan. Various bodies, including the Finance Commission, have advocated the elimination of the plan and non-plan distinction in the budget. I propose to constitute a Task Force, including representatives of Planning Commission, Finance

Ministry, Comptroller and Auditor-General of India and State Governments to examine these issues in a comprehensive manner and to make recommendations for a functionally viable and more focussed presentation of government expenditure in the budget.

49. A related problem is the proliferation of Central Sector and Centrally Sponsored Schemes over the years. There is a need to rationalise these, with the objective of reducing overlaps and duplication, modifying procedures and norms and making them more easily accessible to the intended beneficiary. The Task Force, mentioned above, will also advise on this issue.

# **Development of North Eastern Region**

- 50. The government have already decided to restructure the North Eastern Council (NEC) for speedy implementation of important infrastructural programmes in this region. Sikkim will also be included in the Council. Necessary legislation will be introduced in Parliament to effect these changes.
- 51. Furthermore, it has been decided that a non-lapsable Central Resource Pool will be created for deposit of funds from all Ministries where the plan expenditure on the North Eastern region is less than 10 per cent of the total plan allocation of the Ministry. The difference between 10 per cent of the allocation and the actual expenditure incurred on the North Eastern region will be transferred to the Central Pool, which will be used for funding specific programmes for economic and social upliftment of the North Eastern States.
- 52. The North-Eastern Development Finance Corporation Limited (NEDFi) promoted by public sector financial institutions and banks was incorporated in 1995. NEDFi strives to respond to the specific needs of industries in the North-East. At present there is one State Financial Corporation (SFC) in Assam and twin function Industrial Development Corporations (IDCs) in some other States. In order to foster healthy and efficient growth of these institutions. I am proposing that the refinancing function for industrial loans of SFC/IDCs of the North-East will be undertaken henceforth by NEDFi, rather than IDBI/SIDBI as at present.

# Disinvestment/Privatisation/PSU Reform

53. The regular budget takes credit for a receipt of Rs.5,000 crore from disinvestment in the current year. In order to expedite the process the government have decided to disinvest specified portions of equity from IOC, GAIL, VSNL and CONCOR. As part of an overall strategy to restructure Indian Airlines and expand its capacity, government have decided to restructure the capital of

Indian Airlines and also to undertake a phased disinvestment in this company, over three years, bringing the government's equity holding down to 49 per cent.

- Some public sector undertakings have consistently incurred large losses. Experience and studies by independent organisations; have conclusively established them to be unrevivable. Nevertheless, a decision on their closure has been delayed only on account of the concern for the interest of the workers. In order to find a viable and satisfactory solution to this dilemma, the government have decided to provide a safety net to the workers of enterprises destined for closure by providing a liberal and attractive compensation package prior to closure. At present, when a unit is closed, the workers are only entitled to retrenchment compensation under the Industries (Development and Regulation) Act, which is only 15 days wages for each completed year of service. To make the compensation package attractive, it is proposed to make applicable the benefits of VRS package, namely 45 days wages for each completed year of service, subject to the maximum wage or salary accruable on the basis of the balance of years of service left to all the workers of these public sector units. As a further improvement to the package, the workers of these units will also be eligible for a maximum of 60 months or 5 years salary or wages as compensation in the case of all those who have completed not less than 30 years of service. This would mean that all those who have put in more than 30 years of service will get more than the normal VRS. The other conditions of the VRS will apply and this offer will be made time bound.
- 55. A separate Restructuring Fund is being constituted for this purpose and these public sector enterprises will be advanced funds from the budget to offer a compensation package to the workers. Once the labour is separated, the assets of the company will be available for disposal at the best economic price. The proceeds of the disposal, after settling all pending liabilities, will be credited to the Restructuring Fund which will get recouped to that extent. This would enable the fund to operate on atleast a partially self-sustaining basis and it is expected that, in the course of time, budgetary support for the fund will gradually diminish.
- 56. Government have also decided that in the generality of cases, the government shareholding in public sector enterprises will be brought down to 26 per cent. In cases of public sector enterprises involving strategic considerations, government will continue to retain majority holding. The interest of workers shall be protected in all cases.

## **Budget Estimates for 1998-99**

- 57. As Hon'ble Members are aware details of the revised estimates for 1997-98 were presented along with the interim budget in March 1998. I am, therefore, not going over those estimates again. The figures that are given below are the budget estimates for 1998-99. I shall compare them with the revised estimates for 1997-98, since budget estimates are after all estimates. What really matters is the expenditure in the previous year and the increase proposed in this year's budget.
- 58. I shall now briefly go over the budget estimates for 1998-99.
- 59. For 1998-99, the total expenditure is estimated at Rs.268107 crore. Of this, Rs.72,002 crore has been provided as budget support for Central, States and UT Plans and balance Rs.1,96,105 crore is for non-plan expenditure. Hon'ble Members will be pleased to note that the budget support for the plan has been increased by Rs.11,372 crore from Rs.60,630 crore in revised estimates 1997-98, which is the largest increase ever in absolute terms. Even in percentage terms the 18.8 per cent increase is the highest in the last decade, except for one year.

# Plan Expenditure Central Plan

- 60. Total Central plan outlay at Rs 1,05,187 crore will be higher by Rs.24,154 crore from the last year's level of Rs.81,033 crore. Gross budgetary support for the Central plan is being enhanced from Rs.33,629 crore in the revised estimates 1997-98 to Rs.42,464 crore. The balance will be met by the internal and extra-budgetary resources of the Central Public Sector Enterprises. Gross budgetary support for the Central plan includes provision of Rs.5,741 crore for externally aided projects.
- 61. The plan allocations reflect our dominant priorities. The plan allocation for the Ministry of Agriculture has been increased by 58 per cent from Rs.1807 crore to Rs.2,854 crore.
- 62. For 1998-99, the plan allocation for Ministry of Rural Areas and Employment is Rs.9,912 crore, an increase of Rs.1,556 crore over RE 1997-98 of Rs.8,356 crore
- 63. The plan allocation for Ministry of Health and Family Welfare is Rs.3,684 crore, an increase of 34% over RE 1997-98 of Rs.2,747 crore.
- 64. The plan allocation for the Department of Education has been increased substantially from Rs. 3,351 crore to Rs. 4,245 crore.

- 65. The plan allocation for Ministry of Welfare is being increased by 91 per cent from Rs.804 crore to Rs.1,539 crore. It includes Rs.92 crore for National Backward Classes Finance and Development Corporation, Rs.41 crore for National Minorities Development and Finance Corporation, Rs.60 crore for share capital contribution to State Scheduled Castes Development Corporations. Rs.28 crore for National Handicapped Finance and Development Corporation and Rs.10 crore for National Safai Karmachari Finance and Development Corporation.
- 66. In order to sustain our quest for excellence in frontier areas of scientific research, the plan allocation for Department of Atomic Energy is being enhanced by 68 per cent from Rs.828 crore to Rs.1,391 crore and the plan allocation for Department of Space is being raised by 62 per cent from Rs.850 crore to Rs.1,381 crore.
- 67. For tapping the potential of non-conventional energy sources, the plan allocation for the Ministry of Non-Conventional Energy is being more than doubled from Rs.190 crore to Rs.404 crore.
- 68. The plan allocation for the Ministry of Environment and Forests is being increased by 60 per cent from Rs.440 crore to Rs.704 crore.
- 69. The budgetary support for the Ministry of Civil Aviation and Tourism is being more than tripled from Rs. 122 crore to Rs. 379 crore.
- 70. The plan allocation for the Department of Women & Child Development is being stepped up from Rs. 1,026 crore to Rs. 1,226 crore.

## Central Assistance for States and UTs' Plan

71. I am providing Rs.29,538 crore as Central plan assistance to States and Union Territories in budget estimates 1998-99 compared to Rs.27,001 crore in the revised estimates 1997-98. The normal Central Assistance for State plan is proposed to be enhanced from Rs.12,888 crore to Rs.15,037 crore. The Special Central Assistance for Tribal Sub-Plan is proposed to be enhanced from Rs.330 crore to Rs.380 crore. The Additional Central Assistance for externally aided projects is placed at Rs.5,000 crore. Assistance for Basic Minimum Services and Slum Development schemes is proposed to be enhanced from Rs.2,873 crore to Rs.3,760 crore.

## New schemes

- 72. A new experimental crop insurance scheme is being launched in 24 selected districts to cover non-loance farmers with a provision of Rs.100 crore.
- 73. A new scheme of Technology Mission on cotton is being launched with a provision of Rs.60 crore.
- 74. A new scheme for rehabilitation of tribals displaced from National Parks and project areas is being launched with a provision of Rs.25 crore.

## Non Plan Expenditure

- 75. Total non-plan expenditure in 1998-99 is estimated to be Rs.1,96,105 crore compared to Rs.1,74,615 crore in revised estimates 1997-98.
- 76. The provision for interest payments has increased from Rs.65,700 erore in RE 1997-98 to Rs.75,000 erore.
- 77. The provision for Defence expenditure has been increased substantially from Rs.36,099 erore in RE 1997-98 to Rs.41,200 erore. I will consider further increase in the budgetary support during the course of the year, if necessary. There can be no compromise in our defence preparedness.
- 78. An amount of Rs.9,000 crore is being earmarked for Food subsidy in 1998-99 representing an increase of Rs.1.500 crore over RE 1997-98. The provision for sugar subsidy has been retained at Rs.400 crore. An increase in food subsidy has become necessary due to recent revision of minimum support price for wheat procurement and also to clear arrears pertaining to previous years.
- 79. Pursuant to the change in the selling price of urea, the provision for subsidy on indigenous nitrogenous fertilisers is being reduced from Rs.6,600 crore in RE 1997-98 to Rs.6,000 crore. The subsidy on decontrolled phosphatic and potassic fertilisers is being increased from Rs.2,600 crore in RE 1997-98 to Rs.3,000 crore.
- 80. Grants to States is being enhanced in 1998-99 from Rs.4,114 crore in RE 1997-98 to Rs.6,314 crore representing an increase of Rs.2,200 crore. Of this, the increase of Rs.950 crore is due to assistance to the States for improvement in the pay & allowances of the university and college teachers. The balance of the increase is mainly due to grants under Tenth Finance Commission's award.

- 81. The provision for pension is being increased by Rs.459 crore over RE 1997-98 to Rs.7,342 crore. This provision takes into account the effect of Government's decision to raise the age of superannuation from 58 years to 60 years. This will also have have an impact on the Small Savings Collections. The provision for loans to States and Union Territories against net small savings collections is being kept at Rs.14,200 crore against the provision of Rs.15,732 crore in RE 1997-98.
- 82. A provision of Rs.1,482 crore has been made for nonplan loans to public sector enterprises mainly for payment of salaries and wages to the employees of sick and convalescent PSUs.

## Revenue Receipts

- 83. I shall now turn to the revenue receipts.
- 84. Hon'ble Members are aware that on the basis of a consensus reached in the Third Meeting of the Inter-State Council held on July 17, 1997, the then government had approved in principle to accept the recommendations of the Tenth Finance Commission regarding the alternative scheme of sharing of Centre's tax revenues with the States. I am happy to announce that we have ratified this decision. Accordingly, I propose to shortly introduce a Constitution Amendment Bill to give effect to this alternative scheme subject only to one modification. The modification is that the percentage share of States' share in the gross proceeds of Central taxes may be reviewed by successive Finance Commissions instead of freezing it for fifteen years as suggested by the Tenth Finance Commission.
- 85. Gross tax revenues at the existing rates of taxation are estimated at Rs. 1,48,506 crore. As Hon'ble Members are aware, we had made a provision of Rs.7,594 crore in the RE 1997-98 for States' share in the proceeds of the Voluntary Disclosure of Income Scheme, 1997 as the collections were estimated to be Rs.10,050 crore by March 31, 1998. However, the actual collection is reported to be about Rs.1,000 crore less. After making adjustment for the excess share paid to the States, I am providing Rs.39,074 crore as the share of taxes of the States. Thus, the Centre's net tax revenue will be Rs.1,09,432 crore over RE 1997-98 of Rs.99,158 crore. Non-tax revenues are estimated to increase from Rs.39,356 crore in RE 1997-98 to Rs.45,137 crore this year. I have taken credit for Rs.2,800 crore as license fee from the operators of cellular and basic telecom services and Rs.4,200 crore as net surplus profits of the Reserve Bank of India.

- 86. The net revenue receipts for the Centre, including non tax receipts, are expected to increase from Rs.1,38,514 crore in RE 1997-98 to Rs.1,54,569 crore in 1998-99.
- 87. In the area of capital receipts, market borrowings are placed at Rs.55,931 crore. Net external assistance is estimated at Rs.2,337 crore. I am also taking credit for receipts from disinvestment of equity in public sector enterprises of Rs.5,000 crore.
  - 88. I shall come to the fiscal deficit in Part B of my speech.

## PART B

- 89. Sir, I now present my tax proposals.
- 90. There has been much talk of a tough budget. The temptation to raise taxes in the given situation was indeed great. But I recognise that direct tax policy must impart stability and confidence both to individuals and corporates. Therefore, any uncertainty in this regard must be ended. Tax rates introduced last year are moderate enough. I do not propose to introduce any changes in the rate structure either for individual or corporate taxes. I do hope that long-term stability in tax structure would create virtuous circles of increased productivity, voluntary compliance and enhance our tax widening efforts. In fact, I am going to announce a couple of concessions. Considering the difficulties experienced by the tax payers at the marginal level, the level for tax exemption is being raised from the existing limit of Rs.40,000 to Rs.50,000.
- 91. Salary earners having income upto Rs.1 lakh will be further pleased to know that I propose to raise the ceiling of standard deduction in their case from Rs.20,000 to Rs.25,000. Their pleasure, I hope, will be happily shared by those salary earners whose income is more than Rs.5 lakhs. They will henceforth not be entitled to this deduction. For salary earners having income between Rs.1 lakh and Rs.5 lakhs, no change is proposed in the existing position. I also propose to enhance the ceiling of tax-free reimbursement of medical expenses from Rs.10.000 to Rs.15,000.

- 92. In a country of our size, it is a matter of great anxiety that the total number of assessees constitutes less than 1.25% of our population. The scope for tax widening remains the single most formidable challenge in the area of direct taxes. It is well accepted tenet of taxation policy that moderate rates of taxes only make sense if the net is wide and the scope of evasion progressively minimised. Towards this objective, I propose to take some important initiatives. Last year, a scheme was introduced to cover 12 important cities where if you fulfil two of the four criteria, namely, possession of a house, subscription to a telephone, spending on foreign travel and possession of a motor vehicle, you would be obliged to file an income-tax return. This scheme had several lacunae which I propose to remove. In the first instance, the scheme is being extended now to cover 23 more cities in India taking the total coverage to 35 cities. The net itself is being enlarged to include two additional criteria, namely, holding a credit card and membership of expensive clubs, taking the total parameters to six. Finally, the matching of two out of four parameters apart from being an administratively onerous task provided an escape route to many potential assessees. I believe that if any one fulfils one of the six criteria, it would be reasonable to ask the individual to file his income-tax return. It could thereafter be determined whether he is liable for payment of taxes or not. This revised "Oneby-Six", as the scheme would now be known, is a significant initiative in our tax widening efforts and it is my intention to raise the total number of individuals filing their income-tax returns by at least 50 percent during a full fiscal year.
- 93. Coupled with tax widening, tax evasion continues to be a serious handicap. While efforts at enforcement would be strengthened, I propose to undertake a new initiative in making it obligatory for assessees to quote their PAN or GIR number mandatorily in respect of certain high value transactions. These transactions would be:-
  - Purchase & Sale of immovable property
  - Purchase & Sale of motor vehicles
  - \* Transaction in shares exceeding Rs.50,000
  - Opening of new bank accounts
  - Fixed deposits of more than Rs.50,000
  - Applications for allotment of telephone connection
  - Payment to hotels exceeding Rs.25,000/-.

With increased usage of computerisation, this data will be fully utilised for increasing the tax-base and for preventing the leakage of revenue.

- 94. We must recognise that the cumbersome nature of our income tax forms coupled with complex procedures is a serious deterrent to an honest individual in becoming an assessee. I, therefore, propose to introduce, for the first time, a simple one page taxpayer-friendly return form to be hereinafter called, 'SARAL', applicable to all non-corporate taxpayers. SARAL can be filled up easily without the aid of Chartered Accountants or Tax Advisors. The 'SARAL', I hope, would become popular enough, through voluntary compliance and the assistance of NGOs, which I propose to muster, along with mobile vans for important cities, can be widely distributed and collected easily on spot. This will, apart from contributing to our tax widening effort, also make an important psychological difference in the mindset of potential tax assessees.
- 95. Litigation has been the bane of both direct and indirect taxes. A lot of energy of the Revenue Department is being frittered in pursuing large number of litigations pending at different levels for long periods of time. Considerable revenue also gets locked up in such disputes. Declogging the system will not only incentivise honest taxpayers, enable government to realise its reasonable dues much earlier but coupled with administrative measures, would also make the system more user-friendly. I, therefore, propose to introduce a new scheme called "SAMADHAN". The scheme would apply to both direct taxes and indirect taxes and offer waiver of interest, penalty and immunity from prosecution on payment of arrears of direct tax at the current rates. In respect of indirect tax, where in recent years the adjustment of rates has been very sharp, an abatement of 50 per cent of the duty would be available alongwith waiver of interest, penalty and immunity from prosecution.
- 96. Legal measures are also being proposed to limit and expedite litigation. These include enhanced scale of fees for filing appeals before the Appellate Commissioner and the Income Tax Appellate Tribunal, abolition of the level of Deputy Commissioner (Appeals), provision of direct appeals to High Courts to reduce delay, and also extension of the scope of the Authority for Advance Ruling to notified categories of resident tax payers.
- 97. Moderate rates and large concessions do not go hand in hand. I have, therefore, carried out a review of the various concessions and exemptions under the Income-tax Act. I find that many of them are no longer necessary and some of them are also being used for tax avoidance. I, therefore, propose to withdraw

many of these provisions. These include exemption to the Export Import Bank of India and exemption in respect of certain perquisites of foreigners employed in India. The blanket exemption in respect of educational and medical institutions which is being misused, is proposed to be withdrawn, compelling such institutions to come under a discipline. However, safeguards are being provided to ensure that the institutions genuinely serving the social cause in either field do not lose the existing benefits.

- 98. I also propose to plug certain loopholes. Rule 5(a) of the First Schedule to the Income-tax Act relating to computation of profit of insurance business other than life insurance business is being amended to prevent leakage of revenue. Similarly, section 10(23G) of that Act is being recast to serve the objective of infrastructure financing without misuse of the concession. Under the existing provisions, there is no mechanism to ensure that the tax free funds raised by an infrastructure enterprise are actually used for infrastructure development within a reasonable time and are not used for any other purpose. I propose to provide such a mechanism.
- 99. Gift-tax has been levied in India since 1958. The revenue yield from this tax has been insignificant. Last year we collected barely Rs.9 crore. The Gift-tax Act has also not been successful as an instrument to curb tax evasion and avoidance. I, therefore, propose to discontinue the levy of gift- tax on gifts made after 30th September, 1998. At the same time, to ensure that there are no leakages of income-tax revenue through the mechanism of gifts, I propose to tax the gifts under the Income-tax Act itself in the hands of the recipients. However, the gifts from non-residents including NRIs through banking channels will continue to enjoy exemption as at present.
- 100. I have already said that housing is an area which requires our utmost attention. Therefore, I propose several incentives to encourage house-building activity. These include:-
  - \* Tax holiday for approved housing projects 100 per cent deduction from profits for first five years and 30 per cent deduction for subsequent five years.
  - \* Increased deductions against income from house property deduction for repairs and collection charges increased from 1/5th to 1/4th and deduction for interest on borrowed capital in case of self-occupied property increased from Rs.15,000 to Rs.30,000.

- \* Carry-forward of losses from house property against future income under the same head to be allowed for 8 years.
- Deduction equal to 50 per cent of the profits to companies engaged in housing projects aided by the World Bank.
- \* Section 80GG in respect of deduction for rents paid is being reintroduced.
- \* Exemptions to certain specified properties like commercial complexes under the Wealth-tax Act.
- 101. Other areas in the social sector for which new tax incentives are proposed or the existing ones being increased include employment generation, improvement of environment, upliftment of women, road safety, cooperatives and medical expenses of the handicapped.
- 102. I propose to allow a new deduction to companies with a view to encourage them to employ additional work force. An amount equal to 30 per cent of additional wages paid to the new workmen will be allowed as a deduction against profits, subject to certain conditions.
- 103. For improvement of environment, I propose to allow 100 percent deduction, subject to a ceiling of Rs.5 lakhs, to undertakings engaged in the collection or processing of biodegradable waste. I also propose to make activities which encourage the production of bacteria induced fertilisers eligible for 100 per cent deduction under section 35AC of the Income-tax Act. Necessary amendment in the rules will be notified for this purpose. Similar benefit is proposed to be extended to the activities of establishing and running of educational institutions, hospitals and medical facilities in rural areas exclusively for women and children and also creches and schools for the children of workers employed in factories or at project sites. I also propose similar amendment of rules to make activities which promote road safety and traffic awareness and prevent accidents eligible for 100 per cent deduction under section 35AC.
- 104. The promotion of sports and games in the country needs to be encouraged. I propose setting up of National Sports Fund and further propose that donations made to the Fund will be eligible for 100 per cent deduction.
- 105. I propose to extend 100% tax holiday granted to industrial undertakings located in any industrially backward State or district

till the year 2000. I also propose similar extension of tax holiday to power sector upto the year 2003 and also to new refineries set up after 1st October, 1998. I also propose to extend infrastructure status to inland waterways and inland ports.

- 106. I further propose tax holiday benefits to radio paging services and services provided by satellite owners for telecommunication.
- 107. I also propose several measures in response to demands from business and industry. Certain categories of business reorganisations are proposed to be freed from any additional tax liability or loss of tax benefits keeping in view the necessity of such reorganisation consequent on economic liberalisation. No capital gain would be charged and the benefit of carry-forward of losses and unabsorbed depreciation would be allowed in case of specified reorganisations. Intangible assets are proposed to be allowed depreciation at the rate of 25 per cent. Provisions for amortisation of preliminary expenses are proposed to be liberalised. The period of amortisation is proposed to be reduced from 10 years to 5 years and the rate of deduction will consequently be doubled. Stock lending is proposed to be exempted from capital gains.
- 108. Delay in refund of excess tax collected tantamounts to denial of justice. It is a source of constant harassment, particularly of small tax payers. I intend to mitigate this difficulty by effecting an amendment in section 192 of the Income-tax Act which will enable adjustment of loss from house property against salary income, at the source itself. This, I believe, will eliminate a large number of refund claims.
- 109. In response to demands from tax payers, I propose to take further measures. Under the existing provisions of section 44AA of the Income-tax Act, every person carrying on business or profession is required to maintain account books, if his income from business exceeds Rs.40,000 or his total turnover exceeds Rs.5 lakhs. Considering the increased cost of engaging accountants, I propose to enhance these limits to Rs.1,20,000 and Rs.10 lakhs respectively. I further propose that the penalty leviable at the minimum rate of Rs.100 per day for failure to furnish certificates of tax deduction or collection at source under section 203 or to deliver copies of declarations under section 197A, shall not exceed the amount of tax deductible or collectible, as the case may be. Presently, there is no such ceiling on the quantum of penalty leviable which causes hardship, particularly to small businessmen.

- 110. Certain demands of the film industry have also engaged my attention and I propose to give relief to them. Under the existing rules, if a film is released on commercial basis at least 180 days before the end of the previous year, full amortisation of the cost incurred on production or acquisition of distribution rights of the film is allowed in the year of release itself whereas if the film is released later, full amortisation is not allowed in that year. Considering that nowadays film producers and distributors release a large number of prints simultaneously to counter the threat of video-pirates and cable television, resulting in shorter life span for exploitation of films, I propose to reduce the aforesaid period of 180 days to 90 days. This will enable the film industry to quickly recoup the cost of film production and distribution. I also propose that producers of films, who are required to furnish information in respect of all payments over Rs.5,000 to the Income-tax Department in any financial year would have to do so now only in respect of payments over Rs.25,000. I hope these measures would inspire the film industry to make better and healthier films.
- 111. A controversy has arisen recently regarding the deductibility of payments by way of extortion money. To set the controversy at rest, I propose to explicitly provide retrospectively since the inception of Income-tax Act, 1961 that any money paid by way of extortion will not qualify for deduction as a business expense. As further rationalisation measure, I propose to make certain amendments with regard to block assessment procedure and treatment of MODVAT credit in the valuation of inventories and capital assets.
- 112. The limit of room rent in hotels for the purpose of attracting expenditure tax is proposed to be increased from Rs.1200 to Rs.2000 per day.
- 113. Taxpayers all over the world have a sense of pride in discharging their legitimate dues to the government and the society recognises the important contribution they are making in enabling the State to discharge its responsibilities. In this country, regrettably, the culture of pride by honest taxpayer and a social recognition of his important role has yet to evolve. We must make a change in this mindset. Towards this objective, I propose to introduce a scheme called "SAMMAN" to demonstrate the society's recognition of their important contribution to the national cause. The details of the facilities and recognition to be conferred on the taxpayers and PAN holders would be separately announced.

- 114. I hope the above measures alongwith SARAL, SAMMAN and SAMADHAN will go a long way in making our efforts to increase the tax payers compliance a success. But while we are doing what we can, I call upon the people of India to do their patriotic duty by the country and honestly pay their taxes.
- 115. Before I move on to indirect tax, I would like to state that a large number of suggestions were received from all sections of tax payers and I have got them carefully examined. It is not practicable to acknowledge all these communications individually. I do so now collectively and am extremely thankful to the tax payers for their valuable suggestions.
- 116. Hon'ble Members would see from the budget documents that the figure projected by way of revenue realisation from direct taxes is Rs.48,855 crore which is higher than the figure indicated in the interim budget. This is after taking into account the revenue loss of Rs.950 crore, worked out on a mechanical basis, arising out of certain proposals for reliefs and concessions placed before the House. We intend to make this loss up and collect the budgeted amount through improved collection of arrears, continuation of the tax base enlargement efforts, rigorous enforcement and tightening measures reflected in the budget proposals.
- 117. Mr. Speaker, Sir, our medium-term objective is to enhance the tax-GDP ratio. As far as customs duties are concerned the process of restructuring has resulted in a progressive reduction in tariffs, with a view to align these with internationally acceptable levels, and the broadbanding of rates. These measures have enhanced the competitiveness of Indian industry.
- 118. On the excise side, until a few years ago the regime was characterised by a multiplicity of rates and punctuated with numerous ad hoc exemptions. As a result, the tax structure was opaque. It is the objective of the present proposals to introduce greater transparency in the system through a significant rationalisation of rates. The ultimate objective of this process is to move towards a Central Value-Added Tax (VAT) system which can then be merged with a generalised VAT. It is our intention to move in this broad direction.
- 119. The domestic industry has responded favourably to the restructuring of customs duties and has shown commendable resilience. They need to improve their competitive efficiency to meet the challenges of global competition. But they also have legitimate concerns which cannot be ignored. In this background,

the path of transition has to be carefully calibrated to ensure that the adjustment process for the Indian industry is orderly without leading to serious disruption.

- 120. I have received representations from a cross section of the industry about the regime of import duties. Many Hon. Members have also written to me expressing their concern on the general health of the domestic industry. The demands are diverse and asymmetrical in most cases. This is for obvious reasons. While the users of imported raw materials and other inputs or the consumers of finished imported goods would benefit from further reduction in import duties, the domestic producers have made a convincing case for urgent relief to the domestic industry.
- 121. I have given my earnest consideration to these concerns and the competing claims. I am persuaded about a clear disability that our commodity taxation inflicts on the indigenous goods visa-vis the imported goods. While the former are subjected to sales tax and other local taxes and levies, the import sector escapes them by their very nature. In order to provide a level playing-field to the domestic industry, I propose to impose an additional nonmodvatable levy of 8% on imports which is approximately equal to the burden of local taxes on domestic producers. This duty should not be viewed as a protectionist measure but only as a response to a legitimate demand for a level playing field. The new levy would not apply to crude oil, newsprint, capital goods sector under a special tariff regime or goods which are subjected to additional duties of excise in lieu of sales tax, gold and silver imported by passengers or other nominated agencies and life saving drugs that are free from customs duties. The levy would also not apply to goods which are currently exempt both from basic and additional duties of customs. Similarly, goods imported for subsequent trading have also been left out of its purview, since they bear the burden of Sales tax at the time of first sale. The new levy will also not apply to inputs imported under export-promotion schemes. In addition, there may be other sectors eligible for exemptions. These would be examined and if considered appropriate notified separately.
- 122. The gradual reduction of import duties in the past few years has resulted in certain distortions and anomalies. My proposals seek to correct them as far as found feasible without causing abrupt disruption in the duty structure.
- 123. The steel industry has shown considerable resilience in the past to withstand gradual reduction in customs duties. Last

year, however, the steel industry has not shown any appreciable growth. I propose to increase the customs duty on cold rolled coils of iron and steel from 25% to 30%. I also propose to reduce the duty on stainless steel melting scrap from 10% to 5% and on refractory ceramic goods from 40% to 30%. I am confident that these changes alongwith the imposition of the special additional duty that I have proposed on the imports in general would provide adequate relief to the steel industry.

- 124, The duty on wrought copper is being raised from 30% to 35%.
- 125. I do not intend to make any other changes in the duty structure applicable to ferrous and non-ferrous metals.
- 126. Textile intermediates like DMT, PTA. MEG attract customs duty at 25%. However, caprolactum which is the raw material for making hylon yarn is subjected to a higher duty of 30%. I am reducing the duty on caprolactum also to the level of 25% so that all the major textile intermediates attract the same rate of duty. The import duty on paraxylene, an important input for synthetic fibres and yarn, is being reduced from a total of 15% to 5%.
- 127. The decentralised sector of the textile industry generates avenues for employment. It deserves to be encouraged by reducing cost. I propose to reduce customs duty on apparel grade raw wool from a total of 25% to 20%. The duty on wool waste and garrietted stock of wool is also being reduced by the same extent. I also propose to reduce the duty on acetate and cuprammonium filament yarm from 30% to 20%. In the same vein, machinery required for viscose filament yarm and woollen industry is being accorded the concessional duty of 10%
- 128. The import of paper and paper board has shown phenomenal growth in terms of quantity in order to improve the competitiveness of the domestic producers. I propose to increase the customs duty on paper and paper board from 20% to 30%.
- 129. Mr. Speaker, Sir, my government values the right to information. With a view to further strengthen this right, I propose to reduce austoms duty on standard newsprint from 10% to 5%. I also propose to rationalise the duty structure by subjecting glazed newsprint to the same rate of duty. Furthermore, I also intend to exempt newsprint from the applicability of 8% across the board special additional duty.

- 180. Laiso propose to reduce the duty on light weight coated paper weighing upto 51 grams per square metre for printing of magazines to a total of 5%.
- 131: The customs duty on photographic chemicals is being raised from 25% to 30%. Similarly, the duty on citric acid is being increased from 30% to 40%.
- 132. I propose to reduce the customs duty on jumbo rolls of cinematographic film from 25% to 10%.
- 133. Motor vehicle parts are generally subjected to customs duty at 40%. However, I Coengines and parts thereof for motor vehicles attract a lower rate of 20%. I propose to raise the customs duty thereon to 30%.
- 30% to 20%. This would help the diamond cutting tool industry.
- 135. As a measure of rationalisation, I propose to reduce the duty on rayon-grade wood pulp from 10% to 5%.
- 136. Thalassaemia is a life-threatening blood-disorder. There have been requests for exempting maltol, an input used in the manufacture of drugs for the treatment of this disorder. I propose to fully exempt maltol from customs duty. Hydroxy ethyl starch and dextran are used in the manufacture of artificial plasma which is free from import duty. I propose to reduce the burden of duty on artificial plasma by reducing the duty on hydroxy ethyl strach and dextran from 30% to 5%. I also propose to exempt Lamiyudine, which is used for the treatment of AIDS, from customs duty.
- 137. Leather industry contributes significantly to our export effort. In order to encourage its export. I propose to reduce the duty on specified machinery for leather industry from 20% to 5%. This would also be the rate applicable to leather splitting machinery. Talso propose to reduce the duty on saddle trees from 30% to 10%.
- 138. Sir the House is aware that India has joined the Information Technology Agreement. We are committed to abolish the import duty on products of information technology. This is not because we are bound by the ITA but because we are convinced that spread of information technology and freer exchange of information is the key to success and human welfare. I propose to reduce the duty on floppy disk drives, hard disk drives and CD-ROM drives from a total of 12% to 5%. The duty on ICs of value exceeding one thousand rupees per piece is also being reduced to

5%. I also propose to reduce the duty on computer parts excluding PPCB from a total of 15% to 12%. The duty on PPCB is being reduced from a total of 25% to 22%. I also propose to reduce the duty on cathode ray tubes for colour monitors for computers from a total of 15% to 5% and on deflection components for colour monitors for computers from a total of 25% to 5%. My proposals also include reduction in duty on telecom software from 40% to 30%. Such software henceforth will not be subject to any additional duty of customs.

- 139. In order to encourage the domestic telecom equipment sector, I propose to reduce the duty on parts of such equipment to 20%.
- 140. As a measure of environmental protection, I propose to reduce the import duty on sawn wood and certain other varieties of wood from 30% to 25%. I also propose to reduce the duty on biopesticides, which are eco-friendly, from 30% to 5%. With the same objective, I have proposed reduction of duty on membrane electrolysers and parts from 25% to 10%.
- 141. The duty on spodumene, which is an energy saving material, is being reduced from 25% to 10%. On silicon, which is widely used in solar energy applications. I propose to reduce the duty to half of the existing 10%.

I propose to reduce the duty on -

- Solar cells and modules from 30% to 20%
- Button cells from 20% to 10%
- Watch movements from 25% to 20%
- DC micro motors from 40% to 20%
- \* CD mechanism from 40% to 30%
- 142. Mr. Speaker Sir, good roads are a necessity for social and economic development. I am sure that those of us who are privileged to afford personalised vehicles can afford to contribute to the faster development of good roads in the country. I propose to charge an additional tax at the rate of rupee one per litre on petrol with immediate effect. This is expected to generate an amount of Rs.790 erore in a year which will be used for the development of roads and entirely go towards augmenting the corpus of the National Highways Authority of India. I propose to extend the concessions presently available to import of equipment for construction of National Highways to other road-construction projects also:

- 143. The importers of precious yellow metal can certainly afford to contribute a bit more to the national exchequer. I propose to increase the import duty on gold from 220 rupees per ten grams to 250 rupees per ten grams.
- 144. The duty free allowance for baggage is Rs.6000 at present. Many countries do not impose any such restrictions. While we may not follow them there is need to increase the present limit to reduce delays in clearance of passengers. I propose to increase the baggage allowance from Rs.6000 to Rs.12000 for passengers returning to India after a stay exceeding three days. I also propose to extend free allowance of Rs.3000 to Indian residents returning from Nepal, Bhutan, Myanmar or China by air, after a stay exceeding three days.
- 145. There are a number of items on which it is necessary to reduce the customs duties marginally on account of GATT binding. I do not wish to take the time of the House in going into the details.
- 146. The government is committed to provide a tax code which is consistent with dismantling of administered pricing mechanism of petroleum products in a phased manner. By the year 2001, the import duty on crude has to be reduced from the current level of 27% to not more than 5%. The import duty on down stream products like furnace oil, LSHS, HSD oil, motor spirit and ATF has also to be reduced to the level of 10% to 15%. In this process, we will ensure an effective protection not exceeding 20% for downstream industry by suitable differential and calibration of import duty structure.
- 147. I have initiated the process of implementing the decisions arising from the dismantling of administered pricing mechanism. I propose to reduce the customs duty on crude from a total of 27% to 22%. This is estimated to result in a revenue loss of Rs.965 crore in a year. In order to recoup the loss, I propose to increase the excise duty on motor spirit from 20% to 35%. I also propose to impose customs duty on kerosene imported for parallel marketing at 32%, including special duty of 2%.
  - 148. I now come to my proposals on central excise.
- 149. Mr. Speaker, Sir, the contribution of the small scale sector in the economy cannot be over emphasised. It is a critical fast track for generating employment thus promising support to thousands of families. The predecessor governments have been sympathetic to the small scale sector but I am afraid they have

not done enough to encourage them so as to exploit their full potential. The fiscal incentives provided to the small scale sector have been rather meagre for a number of years.

- 150. I have taken certain important steps in this direction. I propose to raise the exemption limit for excise purpose from Rs.30 lakhs to Rs.50 lakhs, an increase of about 65%. The clearances between Rs.50 lakhs to Rs.100 lakhs shall be charged to a flat nominal rate of 5%. These proposals would result in a revenue loss of Rs.300 crore in a year. This is a small price to pay to restore to health this vital sector of our economy.
- 151. Over the years the scheme of Modvat credit has been considerably liberalised. However, the amount of Modvat credit availed has grown unexpectedly fast in recent years, suggesting misuse of the Modvat credit scheme in the absence of a comprehensive computer net work for cross-checking modvatable invoices from a-flung ranges. Until such a computer network becomes functional, and as a transitional measure, I propose to restrict the availability of Modvat credit by 5% of the duty paid in the case of inputs used in the manufacture of excisable goods. However, no restriction is placed on the Modvat credit in respect of capital goods.
- 152. My proposals regarding other changes in excise duty are guided by the overall need to rationalise the rate-structure so as to reduce the multiplicity of rates and ensure convergence towards a mean rate of 18% ad valorem. An ideal tax structure would be one where, barring the mean rate, there is one lower rate for items deserving concession and a higher rate for what may be described as demerit goods. This would minimise the oscillations in rates and call for compression of intermediate rates.
- 153. As a first step towards a convergence to the mean rate, I propose to impose excise duty of 8% on certain commodities. These include:
  - Packaged tea
  - Branded butter, cheese and ghee
  - Sewing machines, other than hand operated
  - Branded spice's
  - Branded edible preparations when produced in factories
  - Preparations of meat and fish sold under a brand name
  - Skimmed milk powder other than for infant feeding

- Fractors not exceeding 1800 cc
- Spectacle lenses and frames
- Slide fasteners
- 154. I also propose to charge excise duty on exempted articles of plastics at a flat rate of 5% on clearances in excess of Rs. 1 crore in a financial year.
- 155. In the same spirit, I propose to increase the excise duty on medical instruments and appliances as also on pollution control equipment from 5% to 8%.
- 156. A good number of commodities are subject to excise duty at 8%. Some of them can bear a higher duty. I, therefore, propose to increase the excise duty on these commodities to 13%.
- 157. As a result, malt, certain types of cartons, medical furniture, sun glasses and unrecorded audio cassettes will henceforth be subjected to duty at 13%.
- 158. As a measure of rationalisation, I propose to increase the duty on arms and ammunition from 18% to 25%. I, however, assure the House that arms and ammunition for the military services will continue to be exempt from excise duty.
- 159. I propose to raise the duty on multi-utility vehicles from 25% to 30% and on solid or cushion tyres also from 25% to 30%.
- 160. I also propose to raise the duty on marble tiles from Rs.30 to Rs.40 per square metre.
  - 161. My proposals also include reduction of excise duty on:
  - Effluent treatment plants from 13% to 8%
  - \* Diesel engine sets upto 10 HP from 13% to 8%
  - \* Surgical and medical examination gloves from 18% to 8%
  - Potassium iodate from 18% to 8%
  - Electronic calculators from 18% to 8%
  - Pagers from 18% to 13%
  - Cellophane from 25% to 18%.
  - \* PVC compound from 25% to 18%.

162. I propose to exempt 100% wood-free particle boards and fibre boards made from agro-based residues from excise duty. Henceforth, sement bonded particle board, jute particle board,

rice husk board, glass fibre reinforced gypsum board, sisal fibre board and bagasse board will also be free from excise duty. I also propose to exempt blocks and bricks containing more than 25% fly ash, ready mixed concrete, jute blankets and jute felt from excise duty. Henceforth, pultruded jute articles shall also be free from excise duty.

- 163. I propose to exempt recorded audio cassettes from excise duty. I also propose to exempt recorded video cassettes intended for television broadcasting from excise duty. The exemption for computer software will now be broad-banded to cover all software.
- 164. The domestic nylon industry is stagnating for various reasons. I propose to reduce the duty on nylon filament yarn from 30% to 25%.
- 165. Finance Ministers are often criticised by the tax payers for their compulsive habit to increase the burden of taxes. However, such complaint cannot be justified by compulsive smokers. I propose to increase the excise duty on cigarettes by varying degrees ranging from 6% to 11% of the specific rates.
- 166. I have no intention of being harsh on smokers all the way. Accordingly, I propose to reduce excise duty on matches manufactured in the cottage sector by half from Rs.0.50 to Rs.0.25 per hundred boxes. A smaller reduction is also being made in respect of matches manufactured by other sectors.
- 167. High rates of duties are known to induce evasion and avoidance. I propose to reduce the excise duty on alcohol-based toilet preparations from 100% to 50%. I expect that this will improve compliance and States will get more revenue.
- 168. The Maximum Retail Price (MRP) based excise levy introduced last year in respect of certain products has been welcomed by the industry. This scheme provides for simplification and certainty in taxation. I propose to extend this scheme to a few more commodities, such as chocolates, malted food preparations, glazed tiles, razor blades, radio sets, domestic electrical appliances and pan masala.
- 169. In the last budget, a number of services were added in the tax net. These included the service rendered on transportation of goods by road. The House is aware that it led to wide spread resistance and protests. As a result, this service tax was virtually kept in abeyance and rightly so. I have decided to abolish the

service tax on transportation of goods by road. I have also decided to abolish the service tax payable by outdoor caterers and pandal contractors. However, I have proposed service tax on some new services. These are services provided by:

- Architects
- Interior decorators
- Management consultants.
- Chartered Accountants.
- Cost Accountants.
- Company Secretaries
- Private security services
- \* Real estate agents and real estate consultants`
- Market research agencies
- Credit Rating Agencies
- Underwriting agencies
- Slaughter houses using mechanised means for large animals

We will examine how in respect of certain segments liable to Service Tax, the manner and mode of payment could be further simplified to improve compliance. These new service taxes will yield Rs.220 crore in a full year.

- 170. My proposals relating to customs duties are estimated to result in a net gain of Rs.3,304 crore in one year. In case of excise duties, my proposals are estimated to result in gain of Rs.5,009 crore.
- 171. Mr. Speaker, Sir, there can be no two opinions that we must increase the level of voluntary compliance and our tax procedures should be simple, transparent and hassle free. Our tax laws are yet to achieve this objective even though considerable efforts have been made in the past.
- 172. Our laws are not in tune with the need of the times. It is imperative that they should be rebuilt on a comprehensive basis and modified to make them truly modern. I am conscious that it is not an easy task. But it is also not impossible. I have decided to set up an Expert Group to recast the central excise law. It will be my Government's endeavour to bring a new excise law before Parliament in the next budget session of this House.

- 173. The government have also decided to set up a Settlement Commission for settlement of certain categories of disputes relating to customs and excise duties. The details of the scheme are contained in the Finance Bill. I also propose to set up an authority for Advance Tax Rulings for Excise and Customs in view of the need for foreign investors to be assured in advance of their likely indirect tax liability. A bill to this effect will be introduced in Parliament in due course of time.
- 174. Mr. Speaker, Sir, with our courage, determination and conviction, we freed ourselves from the British Raj more than fifty years ago. This year the nation takes pride in celebrating the 50th year of Independence. Our trade and industry, however, is still not free from another Raj, namely, the Inspector Raj. We are committed to put an end to this in the shortest possible time. I am of the view that we owe it to our taxpayers to provide a competent, efficient, sensitive and responsive tax administration. Indeed, it is long overdue.
- 175. There is a widespread feeling that the operation and implementation of excise laws leads to harassment of the assessees. We are earnestly desirous of bringing about systemic changes to remedy the situation. Some of the more important measures that are proposed, are:
  - Minimising the contact points between the officials and assessees
  - \* Reducing areas which require permission or approval
  - \* Providing respectability to orders passed by Commissioner (Appeals) and the Tribunal
  - \* Simplifying the procedure for second appeal in Modvat cases
  - Restricting factory visits by the staff
- 176. I am conscious of the fact that there is strong resentment against the procedures and legal obligations relating to service tax. I have removed a number of obnoxious and deterrent provisions in law. I also propose to abolish several of the redundant and irritating central excise rules very shortly.
- 177. On the customs side, I have decided to strengthen the initiatives already taken in the form of Fast Track Clearance Systems and the Self-Assessment System in import clearance. Computerisation in both Customs and Central Excise departments

will be completed expeditiously so that information can be obtained from the assessees and the importers and exporters through electronic media thereby reducing contact between the assessees and the department.

- 178. I am introducing a new culture of time-bound action by officials of the Customs and Central Excise department. A Citizens' Charter is being released shortly to lay down the citizen's rights and the obligations cast on the customs and excise officials.
- 179. Copies of notifications giving effect to the above changes in customs and excise duties will be laid on the Table of the House in due course.
- 180. Finally, I have something to say on behalf of my Hon'ble colleague, the Minister of Communications. Postal service is highly employment-intensive and salary and allowances constitute a major part of the operating expenses of the postal department. A revision of tariff for postal services has become unavoidable. However, in the interest of the common man and the role of the print media in a democracy, there will be no change in the tariff for postcard and registered newspapers. However, the rate of competition postcard is being raised from Rs.2 to Rs.3, Inland letter from Re.1 to Rs.1.50, letter from Rs.2 to Rs.3 for every 20 gms. or part thereof and parcels from Rs.8 to Rs.10 for every 500 gms. or part thereof. There are also certain other changes which are explained in the Memorandum circulated along with the budget documents. The changes would take effect from a date to be notified after the Finance Bill is passed. The revisions proposed are estimated to yield an additional revenue of about Rs.270 crore in a full year and about Rs.180 crore in 1998-99. Even this modest increase, which is necessary for sustaining postal development, will only partially meet the cost of postal services leaving an uncovered postal deficit of about Rs.695 crore.
- 181. As a result of my tax proposals and the postal tariff revision, total expenditure of the Central government for the year 1998-99 would be marginally reduced to Rs.2,67,927 crore while the net revenue receipts and non-debt capital receipts would increase to Rs.1,76,902 crore. The revenue deficit is placed at Rs.48,068 crore which is 3% of GDP. The fiscal deficit is placed at Rs.91,025 crore which is 5.6% of GDP. With the present state of the economy and in view of the need for expenditure stimulus to growth, I believe further compression is not warranted this year.

182. Sir, it is my firm conviction that in the days to come India will stand tall on the world's stage because of our commitment to democracy and the pursuit of prosperity. I call upon you to join us to strengthen freedom and opportunity, I call upon you to join us to build a better future for every man, woman and child. As we move together and with discipline, the future is ours. In the words of Ramdhari Singh Dinkar:

सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है; ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।

Rise O' warrior march ahead undaunted You are the Creator of future history The stars of the dark night are fading The whole sky belongs to you.

183. Mr. Speaker, Sir, with these words, I commend the budget to this august House.

J. S. MATHUR, Addl. Secy. (Budget)